Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

‘आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय’

वर्ष-21, अंक-13 01-15 जुलाई, 2026 (पाक्षिक) ₹20

प्रधानमंत्री की सेशेल्स की राजकीय यात्रा

‘यह संबंध ऐतिहासिक और दीर्घकालिक है’

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 23 जून, 2026 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को उनके बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन

करोलबाग (नई दिल्ली) में 23 जून, 2026 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के 'बलिदान दिवस' पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन

घाटकेसर (तेलंगाना) में 30 जून, 2026 को भाजपा तेलंगाना प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन

गांधीनगर (गुजरात) में 27 जून, 2026 को सहकारी मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' सेवा का शुभारंभ करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

पटना (बिहार) में 25 जून, 2026 को 'संविधान हत्या दिवस' पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नागपुर में 19 जून, 2026 को अत्याधुनिक 10,000 टन एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस के 'भूमि पूजन समारोह' के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

विषय-सूची

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

सहायक संपादक
विपुल शर्मा
राजीव कुमार

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

प्रसार एवं सदस्यता
अमित सक्सेना

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.org
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

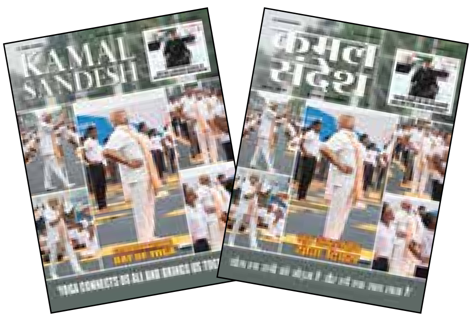

Scan to Download
www.kamalsandesh.org

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

06 **भारत और सेशेल्स के बीच क्षमता विकास, डिजिटल परिवर्तन व रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बनी सहमति**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर 27-29 जून...

09 **आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय : नितिन नवीन**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 25 जून, 2026 को...

12 **प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा डॉ. मुकर्जी के सपनों को साकार करने का प्रयास ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है : नितिन नवीन**

13 **प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में तेलंगाना की धरती पर भी कमल खिलेगा : नितिन नवीन**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 30 जून, 2026 को...

14 **विश्वास, विकास एवं जन-कल्याण के 12 वर्ष: नवाचार एवं जन-भागीदारी का राष्ट्रव्यापी अभियान**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के...

लेख

स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग: जिंदगी में वर्षों का इजाफा / **सी.पी. राधाकृष्णन** 18
फसल से आगे, समृद्धि की ओर / **शिवराज सिंह चौहान** 20
भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण / **मनोहर लाल** 23
जन विश्वास से सुगम होता जीवन / **पीयूष गोयल** 25
लोकतंत्र अमर रहे: स्वतंत्रता को याद रखना क्यों आवश्यक है / **गजेंद्र सिंह शेखावत** 27
नारी शक्ति का दशक, विकसित भारत का उत्कर्ष / **अन्नपूर्णा देवी** 29
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: भारत की सनातन धरोहर से विश्व कल्याण तक / **संजय सेठ** 31

अन्य

प्रधानमंत्री ने तीन अत्याधुनिक जहाजों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को औपचारिक रूप से कमीशन किया 15
भारतीय जनसंघ ही क्यों? 16
भाजपा को जानें 30
मन की बात 33

नरेन्द्र मोदी

हम भारतवासियों ने बार-बार साबित किया है कि जनभागीदारी की ताकत हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे बेहद खुशी है कि पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए मैंने जो आग्रह किए थे, उनका लोगों ने न सिर्फ खुले दिल से समर्थन किया, बल्कि भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं।

(28 जून, 2026)

नितिन नवीन

हमारे जनजातीय समाज ने निरंतर संघर्ष करते हुए अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा की है तथा देश की संस्कृति और विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(29 जून, 2026)

राजनाथ सिंह

भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी क्षमता के दम पर अपनी रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। निजी क्षेत्र, स्टार्ट-अप्स और स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को भी नई गति दे रहा है।

(30 जून, 2026)

अमित शाह

पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को मोदी जी ने गुजरात से लेकर पूरे देश तक चरितार्थ किया है। यही कारण है कि लोगों का भाजपा सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज अहमदाबाद में लोक-दरबार में क्षेत्रवासियों से संवाद किया। जनसेवा को सर्वोपरि रखना हमारा संकल्प है।

(27 जून, 2026)

जगत प्रकाश नड्डा

सबसे खुशी की बात यह है कि जिस 'आयुष्मान भारत' योजना को केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था और आम नागरिकों को इसके लाभ से वंचित रखा था, उसे भाजपा सरकार ने तुरंत लागू किया। आज 48,500 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। मुझे संतोष है कि दिल्ली अब विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रही है।

(30 जून, 2026)

बी एल संतोष

धार्मिक भावनाओं का अपमान... जाली रिपोर्ट बनाना... मामले को दबाने के लिए पुलिस विभाग का उपयोग... तीन मामलों में दोषी... पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसे दिल्ली प्रशासन के तहत हुए 'शराब घोटाले' के माहिर लोग चला रहे हैं, के पास अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास अब बस एक ही रास्ता बचा है कि वे तुरंत त्यागपत्र दें।

(24 जून, 2026)

'विकसित भारत' का मार्ग प्रशस्त करते डॉ. मुकर्जी के आदर्श

भारत ने 23 जून को जब 'बलिदान दिवस' के रूप में मनाया और डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की 125वीं जयंती का उत्सव मना रहा है, तो हम अपने सबसे गौरवशाली सपूतों में से एक डॉ. मुकर्जी को केवल एक राजनीतिक आंदोलन के संस्थापक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी राष्ट्र-निर्माता के रूप में भी याद करते हैं, जिनके आदर्श आज भी 'विकसित भारत' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, राजनेता और राष्ट्रभक्त के रूप में डॉ. मुकर्जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और सिद्धांतनिष्ठ सार्वजनिक जीवन की ऐसी अमिट विरासत छोड़ी, जो आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में जन्मे डॉ. मुकर्जी ने कम आयु से ही असाधारण शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया। मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, जहां उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की सुदृढ़ नींव रखी।

जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक पद से बढ़कर राष्ट्रहित और राष्ट्रीय कर्तव्य सर्वोपरि हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश की एकता, अस्मिता और सुरक्षा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। यही अडिग राष्ट्रवादी सोच उन्हें भारत के महान राष्ट्रनायकों में अग्रणी स्थान दिलाती है। डॉ. मुकर्जी का यह विचार कि सार्वजनिक जीवन पदों और सत्ता के बजाय सिद्धांतों एवं मूल्यों से संचालित होना चाहिए, आज भी असंख्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जनसेवकों को प्रेरित करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और सुशासन पर आधारित एक सशक्त राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता को समझते हुए डॉ. मुकर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने जिन वैचारिक मूल्यों और सिद्धांतों की नींव रखी, वही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ है।

> जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष संवैधानिक प्रावधानों का डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा किया गया दृढ़ विरोध उनके सार्वजनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। उनका ऐतिहासिक नारा— 'एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे'— एक संविधान, एक ध्वज और एक संप्रभु भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। वर्ष 1953 में उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें राष्ट्रीय संकल्प और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया

जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष संवैधानिक प्रावधानों का डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा किया गया दृढ़ विरोध उनके सार्वजनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। उनका ऐतिहासिक नारा— 'एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे'— एक संविधान, एक ध्वज और एक संप्रभु भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। वर्ष 1953 में उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें राष्ट्रीय संकल्प और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। उनका जीवन साहस, त्याग, ईमानदारी और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। एकजुट, सशक्त, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी भारत का उनका स्वप्न आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को प्रेरणा प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। उनकी ही प्रेरणा से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किया गया, नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई, सिंदरी उर्वरक संयंत्र जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पुनः प्रारंभ किया गया तथा 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को शासन की दिशा के रूप में स्थापित किया गया।

साथ ही, देश में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। यह दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की याद दिलाता है, जब वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। उस दौर की स्मृतियां आज भी देश की सामूहिक चेतना में अंकित हैं। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और बिना किसी मुकदमे के हजारों विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों तथा पत्रकारों को जेल में डाल दिया। यही नहीं, संविधान की मूल भावना को भी कमजोर करने वाले अनेक कदम उठाए गए। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किए गए, असहमति को अपराध की तरह देखा गया और जनता की आवाज को कठोरता से दबा दिया गया। भारतीय जनसंघ और लोकतंत्र के अनगिनत रक्षकों के लिए आपातकाल केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि संविधान और भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की रक्षा का अभियान था। हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने उत्पीड़न और कारावास का सामना किया, किंतु स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटे। 'संविधान हत्या दिवस' उन सभी लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है। साथ ही, यह लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा इस मूल सिद्धांत के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है कि कोई भी सरकार संविधान और जनता की सर्वोच्च इच्छा से ऊपर नहीं हो सकती। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

भारत और सेशेल्स के बीच क्षमता विकास, डिजिटल परिवर्तन व रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बनी सहमति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर 27-29 जून तक सेशेल्स की तीन दिन की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया तथा उन्होंने सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित भी किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत-सेशेल्स संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, क्योंकि इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और हमारे विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता में एक प्रमुख भागीदार है।

राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से आधिकारिक वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने 28 जून को माहे द्वीप के विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आधिकारिक वार्ता की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता विकास, डिजिटल परिवर्तन, सतत् विकास, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मत्स्यन, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने भारत द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी को और गहरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

आधिकारिक वार्ता के उपरांत दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक लोगो जारी किया। इसके बाद क्षमता विकास, यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, पोत परिवहन, अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण तथा ऋण सहायता (लाइन ऑफ

क्रेडिट) के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों/समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) की राशि 1,250 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, सेशेल्स की विकास आवश्यकताओं के समर्थन में खाद्य सुरक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में कई घोषणाएं भी की गईं। सेशेल्स ने आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होने की भी घोषणा की।

सेशेल्स के विपक्ष के नेता श्री बर्नार्ड जॉर्जेस ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच विशेष मित्रता को और सुदृढ़ बनाने के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।

मुख्य समझौता ज्ञापन/नवीनीकरण

- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) और सेशेल्स के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय (एमओएफएडी) के बीच समझौता ज्ञापन।
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स के बीच समझौता ज्ञापन।
- जन-औषधि योजना के अंतर्गत मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और सेशेल्स गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और सेशेल्स के मत्स्य, कृषि एवं ब्लू इकोनॉमी मंत्रालय के कृषि विभाग के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सहयोग तथा 2026-2031 कार्य-योजना संबंधी समझौता ज्ञापन।
- भारत और सेशेल्स के बीच प्रत्यर्पण संधि।
- सेशेल्स सरकार और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के बीच अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता।

विकास सहायता

- सेशेल्स सरकार को एक तेज गति वाला गश्ती पोत उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।
- सेशेल्स रक्षा बल को 10 उपयोगी वाहन और लेजर रेडियल श्रेणी की 5 नौकाएं सौंपी गईं।
- सेशेल्स सरकार को 6 एम्बुलेंस सौंपी गईं।
- सेशेल्स सरकार को 500 मीट्रिक टन चावल सौंपा गया।
- सेशेल्स सरकार को 8500 मीट्रिक टन सीमेंट सौंपा गया।

घोषणाएं

- भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक लोगो का अनावरण किया गया।
- व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा केंद्र के लिए वर्चुअल शिलान्यास समारोह।

प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति के विशेष सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से सम्मानित

सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 28 जून को राष्ट्रपति के विशेष सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनके हरित नेतृत्व, विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के प्रयासों और नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और लघु द्वीप विकासशील राज्यों की विकासात्मक आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। यह पहली बार है जब यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी विशेष मित्रता को और मजबूत करने में सहायक होगा। यह सम्मान प्रधानमंत्री की हरित ग्रह के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता— अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली), एक पेड़ मां के नाम, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस- को स्वीकार करता है। यह सम्मान प्रधानमंत्री को सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिए गए कई पुरस्कारों— एफएओ द्वारा दिया गया एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का 'चैंपियन ऑफ द अर्थ' में से एक है।

यह सम्मान हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता विकास, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास की पहलों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को सेशेल्स द्वारा दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। ■

सेशेल्स की नेशनल असेंबली में संबोधन

एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा में वृद्धि करती है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जून को सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच मित्रता के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला तथा लोकतंत्र, विधि का शासन और जन-केंद्रित सुशासन जैसे साझा मूल्यों को रेखांकित किया, जो दोनों देशों का मार्गदर्शन करते हैं।

उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र का जो पहला देश है, जहां मैंने प्रधानमंत्री के रूप में दौरा किया था, वह 2015 में सेशेल्स था। प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी पहली अफ्रीका यात्रा भी थी। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना था कि सेशेल्स हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है।

श्री मोदी ने कहा कि समुद्री पड़ोसियों के रूप में हम मानते हैं कि एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा में वृद्धि करती है। एक की समृद्धि दूसरे की समृद्धि में योगदान करती है और क्षेत्र की स्थिरता से हम सभी को लाभ होता है।

उन्होंने कहा कि यह वर्ष हमारी साझेदारी की मज़बूती का एक शक्तिशाली अनुस्मारक प्रदान करता है। पचास साल पहले, आपकी आजादी की शुरुआत में, एक भारतीय नौसैनिक जहाज 'आईएनएस नीलगिरि' दोस्ती और एकजुटता के प्रतीक के रूप में पोर्ट विक्टोरिया में मौजूद था और आज आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक आपके साथ स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाने के लिए पोर्ट विक्टोरिया में मौजूद हैं।

श्री मोदी ने कहा कि यह सेशेल्स को एक छोटा द्वीप देश नहीं, बल्कि एक बड़ा महासागरीय देश बनाता है। समुद्री अर्थव्यवस्था के वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा बनने से बहुत पहले सेशेल्स पहले से ही इसका नेतृत्व कर रहा था। चाहे समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा करना हो या ब्लू बॉन्ड्स जैसे नवाचारों को आगे बढ़ाना हो, आपके देश ने महत्वपूर्ण वैश्विक वार्तालापों को आकार देने में सहायता की है। साथ मिलकर हम मत्स्य पालन, समुद्री विज्ञान, तटीय प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पर्यटन में साझेदारी कर सकते हैं।

- सेशेल्स तटरक्षक बल के लिए पीएस ज़ोरोस्टर के नवीनीकरण का कार्य पूरा हुआ।
- ग्लास कॉकपिट के साथ एक डोर्नियर विमान का अपग्रेडेशन।
- सेशेल्स का आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल हुआ।

प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जून को सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। श्री मोदी सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

इस वर्ष सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और यह भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की भी 50वीं वर्षगांठ है। इन विशेष अवसरों को यादगार बनाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों ने सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय परेड में भाग लिया। भारतीय टुकड़ी में असम राइफल्स, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना की मार्चिंग बैंड के जवान शामिल थे, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को दर्शाते हैं। समारोह के अंतर्गत और स्थापित परंपरा के अनुरूप भारतीय नौसेना के जहाज तरकश और इक्षक पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंचे।

समारोह में प्रधानमंत्री की भागीदारी दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और दीर्घकालिक मित्रता को दर्शाती है। ■

संविधान हत्या दिवस (25 जून)

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय : नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 25 जून, 2026 को 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए 'एक्स' पर लिखा कि 25 जून, 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं पर सुनियोजित हमला था। श्री नवीन ने लिखा कि सत्ता बचाने की लालसा में देश की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों, राष्ट्रवादी संगठनों और करोड़ों देशवासियों के संघर्ष ने अंततः लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। श्री नवीन ने लिखा कि 'संविधान हत्या दिवस' हमें उस दौर की याद दिलाने के साथ-साथ संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति सतत सजग रहने का संकल्प भी प्रदान करता है।

श्री नवीन ने कहा कि 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद राष्ट्रहित नहीं, बल्कि सत्ता हित को प्राथमिकता दी गई। एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी सहित हजारों लोकतंत्र सेनानियों को जेलों में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और मिसा जैसे कानूनों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया गया। यह केवल राजनीतिक संकट नहीं, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार था।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे लिखा कि सत्ता को निरंकुश बनाने के लिए संविधान में कई संशोधन किए गए। न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास हुआ, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को दबाया नहीं जा सका। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के युवाओं और

आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था: नरेन्द्र मोदी

"आज (25 जून) हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक 'आपातकाल' के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा की। आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। इसके दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया; राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन संस्थानों पर हमला किया गया जो हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। साथ ही, इसने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा। हम सभी के लिए हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सदा प्रतिबद्ध रहे।"

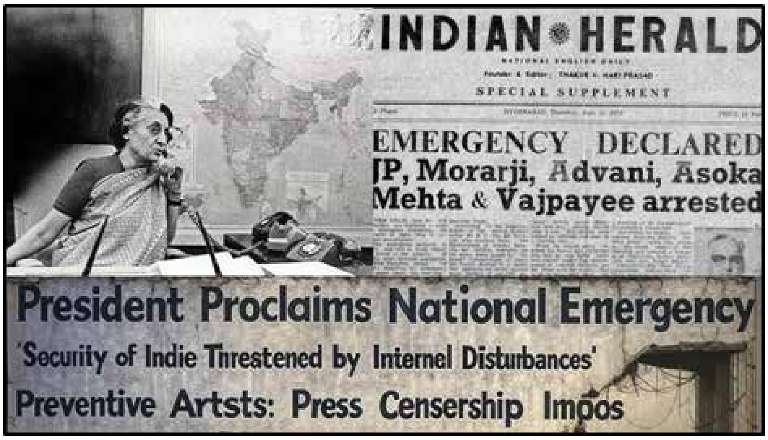

आम नागरिकों ने एकजुट होकर इस तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उसी संघर्ष के दौर में एक युवा प्रचारक के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने गिरफ्तारी से बचते हुए भेष बदलकर आंदोलन का संदेश घर-घर पहुंचाया। भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रहित और लोकतंत्र की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अपने व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक हितों से ऊपर उठकर स्वयं को जनता पार्टी में विलीन कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा का कार्य किया, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने छात्र शक्ति को संगठित कर जनजागरण का नेतृत्व किया। यह त्याग, समर्पण और राष्ट्रनिष्ठा भारतीय राजनीति का स्वर्णिम अध्याय है।

श्री नवीन ने कहा कि आज देश एक विचित्र विडंबना देख रहा है। जिन्होंने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया, वही आज लोकतंत्र के सबसे बड़े स्वयंभू रक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनावों में जनता उन्हें नकार देती है, तब उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहता। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। जब न्यायालयों के निर्णय उनके राजनीतिक हितों के अनुरूप नहीं होते, तब न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। कांग्रेस की राजनीति आज जवाबदेही की नहीं, बल्कि दोषारोपण की राजनीति बनकर रह गई है। संसद नहीं चले तो दोष सरकार का, चुनाव हार जाएं तो दोष व्यवस्था का, जनता समर्थन न दे तो दोष संस्थाओं का। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो दल आज संविधान की दुहाई देता है, उसने आज तक आपातकाल के लिए देश से बिना शर्त माफी क्यों नहीं मांगी? यदि सचमुच संविधान की चिंता होती, तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या के उस अपराध के लिए देश से क्षमा मांगी जाती। दशकों तक आपातकाल के इस काले अध्याय को देश की सामूहिक स्मृति से मिटाने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और संविधान पर हुए इस प्रहार को इतिहास के हाशिये पर धकेल दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लेकर इतिहास के साथ न्याय किया गया। संविधान हत्या दिवस हमें केवल अतीत की

याद नहीं दिलाता, बल्कि यह संकल्प भी कराता है कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सभी को सदैव सजग और समर्पित रहना पड़ेगा। ■

मुख्य बिंदु

- 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं पर सुनियोजित हमला था
- आपातकाल के लिए कांग्रेस ने आज तक देश से बिना शर्त माफी नहीं मांगी, जबकि वही आज लोकतंत्र की दुहाई देती है
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय इतिहास के साथ न्याय करने वाला कदम है
- सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला और मौलिक अधिकार निलंबित किए
- लोकतंत्र सेनानियों, भारतीय जनसंघ, संघ और छात्र शक्ति के संघर्ष ने तानाशाही को पराजित कर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की

सरकार संविधान को अक्षरशः व उसकी भावना दोनों बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: राजनाथ सिंह

"1975 में आज ही के दिन भारत में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। उस दौरान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, न्यायपालिका को नियंत्रित व कमज़ोर करने की कोशिशें हुईं और लाखों नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। आपातकाल हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता में बैठे लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं, तो नागरिकों का जीवन, लोकतांत्रिक संस्थाएं और संवैधानिक मूल्य गंभीर ख़तरे में पड़ जाते हैं। इसलिए, यह दिन न केवल अतीत को याद करने का मौका है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों व आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार संविधान को अक्षरशः व उसकी भावना दोनों बनाए रखने और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश उन सभी लोगों का ऋणी है जिन्होंने आपातकाल के अन्याय और ज्यादतियों का विरोध किया और साहसपूर्वक लोकतंत्र व संविधान की रक्षा की।"

25 जून, 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है: अमित शाह

"25 जून, 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता के अहंकार तथा लालच ने संविधान की आत्मा, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का प्रयास किया था। 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर लोकतंत्र के उन सभी सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। मोदी सरकार द्वारा 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का उद्देश्य इस काले अध्याय को राष्ट्र की स्मृति में जीवित रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर ऐसा आघात कभी दोबारा न कर सके।"

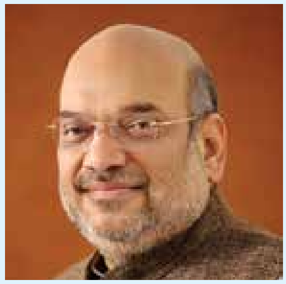

कांग्रेस सरकार ने नागरिक अधिकारों का गला घोंटते हुए देश पर आपातकाल थोपा था : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जून, 2026 को पटना, बिहार में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री नड्डा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि 25 जून, 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का गला घोंटते हुए देश पर आपातकाल थोपा था। श्री नड्डा ने कहा कि बिहार की धरती लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्ष की जन्मस्थली रही है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने देश को तानाशाही के विरुद्ध संगठित करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक श्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह तथा पटना महानगर अध्यक्ष श्री रूपक नारायण मेहता सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि 25 जून वह दिन था, जब प्रजातंत्र का गला घोंटा गया, प्रेस का गला घोंटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाई गई और संविधान पर कुठाराघात किया गया। यह सब हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज इसे इसलिए याद किया जाता है, ताकि भारत का प्रजातंत्र उसी मजबूती के साथ हमेशा कायम रहे, जिस मजबूती के साथ उसने उस समय प्रजातंत्र का गला घोंटने वालों को जवाब दिया था और इस पर कभी कोई आंच न आए। इसके लिए हम सभी प्रतिज्ञा भी करते हैं। यह आने वाली सरकारों और आने वाली जम्हूरियत के लिए भी एक उदाहरण है कि इस प्रकार का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है और भारत की जनता किस प्रकार जागृत होकर जवाब देती है।

उन्होंने कहा कि जस्टिस जगमोहन ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था और कहा था कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है तथा सरकार का दुरुपयोग किया है। इसी कारण उन्हें पद से हटाया गया और उनकी सदस्यता समाप्त की गई। यह बात हम सबको मालूम है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इस घटना के तीन सप्ताह के भीतर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। वह इमरजेंसी लगभग 21 महीने तक चली और वह सब भी हमने अपनी आंखों से देखा है। यदि इमरजेंसी की चर्चा की जाए, तो यह जानना जरूरी है कि 1 लाख 31 हजार लोगों को बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के जेल में डाल दिया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे आंदोलन के दौरान भी अंग्रेजों ने कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में नहीं डाला, जितना इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने डाल दिया। ■

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी बलिदान दिवस (23 जून)

प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा डॉ. मुकर्जी के सपनों को साकार करने का प्रयास ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है : नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 23 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के बलिदान दिवस पर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी. एल. संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं श्री दुष्यंत गौतम, पार्टी के राष्ट्रीय संगठक श्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, लोकसभा सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

श्री नवीन ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के 73वें बलिदान दिवस पर हम उन्हें अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं। वे एक प्रखर राष्ट्रवादी, महान चिंतक तथा देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जो सपना देखा और जिन उद्देश्यों के लिए बलिदान दिया, उसकी सार्थकता आज सभी के सामने दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनना इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब जैसे क्षेत्रों की सीमाओं की रक्षा तथा वहां की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने जो संघर्ष और बलिदान दिया था, उसकी भावना आज भी प्रासंगिक है। पश्चिम बंगाल, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी की जन्मभूमि है, आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ खड़ा है।

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने वर्ष 1951 में जिस सोच और भावना के साथ जनसंघ की स्थापना की थी, वह एक राष्ट्रवादी विचारधारा को नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प था। आज भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता उसी राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं।

श्री नवीन ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने भारत के लिए जो सपना देखा था, उसे साकार करने का कार्य आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उनके सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 23 जून, 2026 को दिल्ली के करोलबाग में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के 73वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। श्री नवीन ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के जीवन चरित्र का परिचय देते हुए भारत सरकार में मंत्री पद का त्याग कर राष्ट्रहित में जनसंघ की स्थापना करने से लेकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए किए गए आंदोलन तथा उनके जीवन बलिदान का उल्लेख किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज तथा अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री नितिन नवीन ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी एक दृढ़ राष्ट्रवादी, विचारक तथा देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जिस भारत का स्वप्न देखा था और जिन आदर्शों के लिए अपना बलिदान दिया, उसकी सार्थकता आज स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने वर्ष 1951 में जिस दृष्टि और उद्देश्य के साथ जनसंघ की स्थापना की थी, वह राष्ट्रवादी विचारधारा को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प था। आज भारतीय जनता पार्टी उसी राष्ट्रवादी विचार के साथ भारत की प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो चुकी है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने भारत के लिए जो स्वप्न देखा था, उसे साकार करने का कार्य आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके सपनों और उद्देश्यों को साकार करने का प्रयास ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ■

भाजपा, तेलंगाना प्रदेश कार्यकारिणी बैठक

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में तेलंगाना की धरती पर भी कमल खिलेगा : नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 30 जून, 2026 को तेलंगाना के औशापुर में आयोजित तेलंगाना प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया तथा 'विकसित भारत' और 'विकसित तेलंगाना' के संकल्प को दोहराया। श्री नवीन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वादाखिलाफी और परिवारवाद के आरोप लगाए। श्री नवीन ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को जनविरोधी बताते हुए भाजपा को जनाकांक्षाओं का विकल्प बताया और कहा कि वर्ष 2028 में तेलंगाना में भी कमल की सरकार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती डी.के. अरुणा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं तेलंगाना के प्रभारी श्री सुनील बंसल, तेलंगाना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री एन. रामचंद्र राव, केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और श्री बंडी संजय कुमार, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मण सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री नवीन ने कहा कि हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया गया है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की कल्पना को साकार करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का तिरंगा शान से लहराए और उसकी गरिमा के साथ कोई गुस्ताखी न कर सके, इस संकल्प को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। यदि आज सुशासन की सरकार की बात होती है, तो पिछले 12 वर्षों में जिस प्रामाणिकता और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कार्य कर रहे हैं, उसके कारण विपक्ष में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह केंद्र सरकार के किसी एक मंत्री पर भी दाग लगा सके। यही भारतीय जनता पार्टी के सुशासन वाली सरकार की पहचान है।

उन्होंने कहा कि हम यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आने वाले वर्षों के संघर्ष के लिए आह्वान करने आए हैं। यदि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना देखा है, तो उसे साकार करने के लिए इस कालखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी अपना पुरुषार्थ करना होगा तथा समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी को केवल दो सीटें मिली थीं, तब भी पार्टी ने संघर्ष को अपना साथी चुना था तथा संगठन को अपना मार्ग और अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर आगे बढ़ी थी। पार्टी को विश्वास था कि यदि वह जनता का विश्वास जीतेगी, तो एक दिन भारत की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जब पार्टी केवल दो सीटों तक सीमित थी, तब भी वह विचलित नहीं हुई। पार्टी की नीतियों और विचारों में कोई भटकाव नहीं आया। उस समय भी पार्टी ने 'जहां हुए बलिदान मुकर्जी, वह कश्मीर हमारा है' का संकल्प लिया था और उस सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे संगठन के रूप में आगे बढ़ती है, जो तप, त्याग और परिश्रम के बल पर परिणाम प्राप्त करने का संकल्प लेकर कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक वातावरण बना है और लोग पूछते हैं कि क्या बदला है? वर्ष 2014 से पहले का भारत निराशा, भ्रष्टाचार और अनिश्चितता के माहौल से घिरा हुआ था। उस समय युवा पीढ़ी के मन में यह प्रश्न था कि उसका भविष्य और भारत का भविष्य क्या होगा। लेकिन आज का युवा और देश के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसी शख्सियत कोरोना जैसी आपदा में भी देश को सभी चुनौतियों से बाहर निकालने में सक्षम है। यदि विदेशी ताकतें भी भारत के सामने खड़ी होती हैं, तो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता भी देश के पास है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिस प्रकार मजलिस, कांग्रेस और बीआरएस की राजनीति चलती है, उसके बीच हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरह से विरोध करती है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तब धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और उसका लाभ एससी, बीसी तथा एसटी समाज के लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा समाज के उन वर्गों को आगे लाना चाहती है, जिन्हें आज भी विकास की मुख्यधारा में लाने का दायित्व शेष है।

श्री नवीन ने कहा कि जिस प्रकार अंग, बंग और कलिंग की धरती पर कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार अब त्रिलिंग की धरती पर भी कमल का पूर्ण वैभव देखने को मिलेगा। ■

मुख्य बिंदु

- कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पर्याय हैं। अब तो राजनीति का अपराधीकरण भी कांग्रेस की नीति बन गई है
- मजलिस, कांग्रेस और बीआरएस में यदि किसी एक विषय पर समानता है, तो वह भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादाखिलाफी है। बीआरएस भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ग्रस्त है
- तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया जाएगा
- जिस प्रकार अंग, बंग और कलिंग की धरती पर कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार अब मोदीजी के नेतृत्व में त्रिलिंग यानी तेलंगाना की धरती पर भी कमल खिलेगा

विश्वास, विकास एवं जन-कल्याण के 12 वर्ष

नवाचार एवं जन-भागीदारी का राष्ट्रव्यापी अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर '12 साल— विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के' नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाया गया, जिसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह ने दी। यह अभियान केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन-जन तक पहुंचने की एक व्यापक पहल बन गया। इसके माध्यम से समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, नागरिक कल्याण तथा राष्ट्र-निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्यों और जिलों में आयोजित विभिन्न नवाचारपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान ने लाखों नागरिकों को सरकार की विकास यात्रा से सफलतापूर्वक जोड़ा तथा 'विकसित भारत' के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान की।

इस अभियान की शुरुआत देश के सभी 37 संगठनात्मक क्षेत्रों में 20 से 27 मई, 2026 के बीच आयोजित संगठनात्मक कार्यशालाओं की शृंखला के साथ हुई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य पिछले बारह वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना, जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना तथा भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति तैयार करना था।

इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक 'एक पेड़ मां के नाम' देशव्यापी अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2026) के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन था। छात्रों, शिक्षण संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और स्वयंसेवकों सहित आम नागरिकों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मीडिया से संवाद भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। सरकार की विकास संबंधी उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए देशभर में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश में आयोजित एक उल्लेखनीय कार्यक्रम में लगभग 450 पत्रकारों ने भाग लिया, जिससे पिछले बारह वर्षों की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने तथा मीडिया के साथ रचनात्मक संवाद स्थापित करने का अवसर मिला।

इस अभियान के दौरान 10 जून, 2026 का दिन विशेष महत्व का रहा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री बने। इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर में प्रार्थना सभाओं और समाजसेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिरों, गुरुद्वारों, बौद्ध मठों, रविदास मंदिरों तथा वाल्मीकि मंदिरों में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए प्रार्थनाएं, हवन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए।

जनसंपर्क इस अभियान का प्रमुख आधार रहा। दिल्ली में 624 गैर-सरकारी संगठनों तथा हजारों स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी से यमुना के 28 घाटों पर एक साथ व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। भजन-कीर्तन, सामुदायिक भोज तथा पेयजल वितरण जैसे सेवा कार्यक्रमों ने सामाजिक सद्भाव और नागरिक दायित्व के प्रति अभियान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 42,000 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों तक पहुंच बनाई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुद्धिजीवियों, पेशेवरों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं से संबंधित साहित्य वितरित किया।

महाराष्ट्र में मॉल और रेलवे स्टेशनों सहित 409 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनमें पिछले बारह वर्षों के दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

इस अभियान की सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक विभिन्न राज्यों में आयोजित 'जन कल्याण शिविर' रहे। अकेले मध्य प्रदेश में 726 शिविरों के माध्यम से 25 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की गई तथा लगभग 94 प्रतिशत मामलों का समाधान किया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसी प्रकार के कल्याणकारी शिविर आयोजित किए गए, ताकि सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें, शिकायतों का त्वरित समाधान हो तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक सरलता से पहुंच सके।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी इस अभियान का एक प्रमुख केंद्रबिंदु रहा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जबकि जयपुर में आयोजित एक विशाल कार्यशाला में लगभग 5,500 लोगों ने भाग लिया।

इस अभियान का समापन 21 जून, 2026 को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रव्यापी आयोजन के साथ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर लगभग 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। योग दिवस से पूर्व देशभर में 7,000 से अधिक योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया गया तथा लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

'12 साल— विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के' अभियान ने यह प्रदर्शित किया कि सक्रिय जनभागीदारी, नवाचारपूर्ण जनसंपर्क, पर्यावरण संरक्षण, समाजसेवा तथा पारदर्शी संवाद के माध्यम से सुशासन को किस प्रकार और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। विकास की उपलब्धियों को नागरिक सहभागिता के साथ जोड़ते हुए इस अभियान ने आत्मनिर्भर, समावेशी और 'विकसित भारत' के संकल्प को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान की। ■

प्रधानमंत्री ने तीन अत्याधुनिक जहाजों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को औपचारिक रूप से कमीशन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की समुद्री तैयारी और स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई मजबूती प्रदान करते हुए 21 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना के प्रथम पंक्ति के तीन अत्याधुनिक जहाजों को कमीशन किया। इनमें बहु-उद्देशीय क्षमताओं से लैस आईएनएस दूनागिरी, एक विशाल सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और उथले पानी के पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत आईएनएस अग्रय शामिल हैं। ये अत्याधुनिक जहाज देश की परिचालन क्षमताओं, भू-राजनीतिक खतरों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में स्थितिजन्य जागरूकता को काफी बढ़ाएंगे।

आईएनएस दूनागिरी

इस तीन-तरफा कमीशनिंग के केंद्र में आईएनएस दूनागिरी है, जो प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरी श्रेणी का पांचवां और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। अपने पूर्ववर्ती जहाज के आधुनिक स्वरूप के रूप में यह युद्धपोत स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और युद्धक तत्परता के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। मॉड्यूलर निर्माण तकनीक से तैयार यह युद्धपोत सुपरसोनिक सतह-से-सतह मिसाइलों, उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों, मीडियम-रेंज गन, क्लोज-इन वेपन सिस्टम तथा अत्याधुनिक पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमताओं से लैस है। इसे उच्च-स्तरीय समुद्री अभियानों और बहुआयामी युद्धक भूमिकाओं के लिए तैयार किया गया है।

आईएनएस संशोधक

आईएनएस संशोधक विशाल सर्वेक्षण पोत श्रेणी का चौथा जहाज है, जो भारत के 'मैरीटाइम विजन 2030' को सशक्त बनाता है और भारतीय नौसेना की कूटनीतिक तथा सकारात्मक भूमिका को विस्तृत करता है। इसके बेड़े में शामिल होने से समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, तटीय और अपतटीय विकास को गति मिलेगी तथा भारत के महासागर दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यह पोत अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र-विज्ञान प्रणालियों के साथ-साथ चार सर्वे मोटर बोट्स (एसएमबी) से सुसज्जित है। ये प्रणालियां अत्यंत सटीक हाइड्रोग्राफिक डेटा उपलब्ध कराती हैं, जिससे समुद्री संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है और उभरती हुई 'ब्लू इकोनॉमी' को मजबूती मिलती है।

आईएनएस अग्रय

तीसरा जहाज आईएनएस अग्रय भारतीय नौसेना की उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बी-रोधी व माइन वॉरफेयर क्षमताओं को और सुदृढ़ करता है। यह उथले पानी के पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) शृंखला का पांचवां पोत है। आईएनएस अग्रय अत्याधुनिक सोनार, टॉरपीडो, पनडुब्बी-रोधी रॉकेट तथा उन्नत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है। तटीय व कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों में तीव्र एवं प्रभावी संचालन के लिए डिजाइन किया गया यह वॉटरजेट-चालित पोत पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उन पर सटीक कार्रवाई करने की उत्कृष्ट क्षमता रखता है। इसकी उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियां इसे तटीय सुरक्षा तथा पनडुब्बी-रोधी अभियानों के लिए एक अत्यंत सक्षम जहाज बनाती हैं। ■

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मिली मंजूरी

भारत सरकार की 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष' के प्रति कुल प्रतिबद्धता अब 60,000 करोड़ रुपये हुई

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में भारत की निवेश प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के नए और आगामी कोषों के लिए भारत सरकार की ओर से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। इससे एनआईआईएफ के लिए भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता 60,000 करोड़ रुपये हो गई।

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) भारत का संप्रभु-आधारित कोष है, जिसका संचालन और प्रबंधन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) की ओर से पेशेवर तरीके से किया जाता है। भारत सरकार एनआईआईएफ में 49% शेयरधारक है और वर्तमान में यह अपने कोषों और निवेश रणनीतियों में लगभग 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्रतिबद्धता का प्रबंधन करती है। एनआईआईएफ ने पूंजी के इस्तेमाल और प्राप्ति में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, और बड़े पोर्टफोलियो से बाहर निकलने के माध्यम से निवेशकों को लगभग 12,000 करोड़ रुपये लौटाए हैं।

एनआईआईएफ ने प्रमुख संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाई है, जिनमें सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, बहुपक्षीय विकास और अग्रणी घरेलू वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इनमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ऑस्ट्रेलियनसुपर, सीपीपी इन्वेस्टमेंट्स, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स, टेमासेक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

ये निवेशक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई भौगोलिक क्षेत्रों से आते हैं, जो भारत की विकास यात्रा और एनआईआईएफ के शासन और वाणिज्यिक ट्रैक रिकॉर्ड में मजबूत अंतरराष्ट्रीय विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ■

भारतीय जनसंघ ही क्यों?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन (कानपुर, 29 दिसंबर, 1952) में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा दिए गए भाषण का द्वितीय भाग

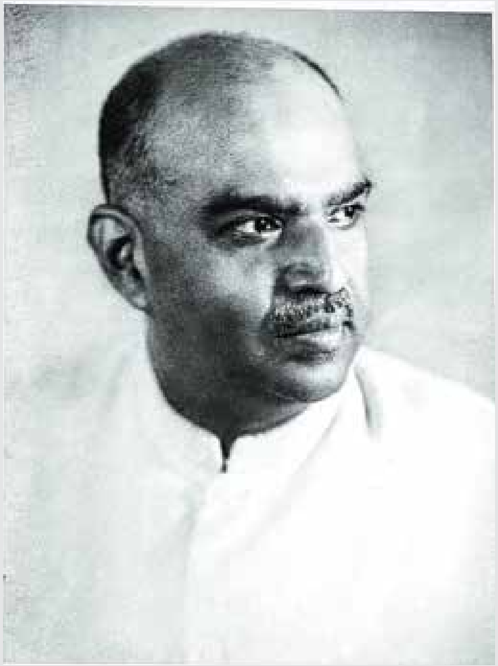

प्रत्येक कार्य के अधीक्षण की पूर्ण व्यवस्था चाहिए और समय-समय पर उसकी प्रगति का पूरा विवरण जनता को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के सभी सार्वजनिक कार्यों का वातावरण नीचे से उपर तक सुव्यवस्था तथा सहकारिता से परिपूर्ण हो, जिसका परिणाम ऊपर से नीचे तक सभी पर हो ताकि वे जनहितैषी राज्य की उच्चतम धारणाओं का योग्य रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। इस समय उत्पादन तथा वितरण की अनेक इकाइयां निजी व्यवस्था के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। अनेक असुविधा के कारण वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं। यदि उन्हें राज्य की ओर से उचित सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त हो तो वह भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में तथा बेरोजगारी के बढ़ते हुए संकट को रोकने में सहायक हो सकती हैं।

विभाजन के पश्चात की समस्याओं में से तीन विषयों पर जनता का ध्यान हाल ही में बहुत अधिक केन्द्रित हुआ है। वे हैं काश्मीर, पूर्वी बंगाल और पुनर्वास की समस्या।

काश्मीर

काश्मीर के विषय में हमारे दल ने यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू तथा काश्मीर का पूरा राज्य भारत का अविभाज्य अंग है। आरंभ में सुरक्षा परिषद् में इस समस्या को ले जाने के कारण कुछ भी रहे हों, गत तीन वर्षों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस प्रश्न को वहां से वापिस ले लेना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस विषय में भारत सुरक्षा परिषद् से किसी भी प्रकार के न्याय की आशा नहीं कर सकता। यद्यपि पाकिस्तान काश्मीर की भूमि का आक्रांता है तो भी भारत के न्यायमुक्त अधिकार का समर्थन करने में एक विचित्र प्रकार की उदासीनता दिखाई देती है। इस प्रकार का आचरण कुछ महाशक्तियों द्वारा जान-बूझकर किया जा रहा है, जिनमें यू.एस.ए. और ब्रिटेन भी सम्मिलित हैं। कुछ समय पूर्व काश्मीर में बनी संविधान सभा को यह चुनौती दी जा चुकी है कि जहां तक जम्मू का सम्बन्ध है वह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यह होते हुए भी इस सभा को भारत में मिलने के प्रश्न को अन्तिम रूप से तय करना चाहिए। यह निर्णय हो जाने के पश्चात् दो प्रश्न ही प्रमुख रूप से रह जायेंगे एक तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू तथा कश्मीर के प्रदेश के भविष्य के विषय में और दूसरे भारतीय संविधान के इस राज्य पर लागू होने के बारे में। प्रथम के सम्बन्ध में जम्मू-काश्मीर सहित सारे भारत का सम्मान यह मांग करता है कि शत्रु के हाथों से इस प्रदेश को छुड़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भारत को किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। यदि एक बार भी हमने प्रदेश पर इस प्रकार बलात् अधिकार स्वीकार कर लिया तो भविष्य में हमारी स्वतंत्रता को भारी संकट खड़ा हो जायेगा।

दूसरे विषय के सम्बन्ध में हम अपने विचार पिछले अवसरों पर खुलकर प्रकट कर चुके हैं। हमारे इस मत के कारण भारत के कितने ही तथाकथित मित्रों और हितैषियों ने हमें गलत समझा है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जम्मू तथा काश्मीर का भारत के साथ विलय सच्ची राष्ट्रीय भावना के अनुरूप तथा काश्मीर सहित भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। काश्मीर के शेख अब्दुल्ला तथा अन्य लोग हमारे संविधान की रचना में भागी थे, जो प्रत्येक प्रकार से मुसलमानों की बहुसंख्या उसी संविधान को उसी प्रकार स्वीकार करने में हिचकिचाती है जिस प्रकार कि वह सारे स्वतन्त्र भारत पर लागू किया गया है। इस विषय पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। एक तर्क यह दिया जाता है कि हमारे संविधान में ही ऐसी व्यवस्था है कि सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात एवं परिवहन के अतिरिक्त संविधान में की धाराओं का लागू होना जम्मू तथा काश्मीर सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। लोग भूल जाते है कि इस विशेष धारा को प्रस्तावित करते हुए भी गोपाल स्वामी आयंगर ने स्वयं ही उस विशेष परिस्थिति का उल्लेख किया था जिसमें से यह राज्य उस समय गुजर रहा था और यह भी असंदिग्ध रूप से कह दिया था कि कानूनी धारा कुछ भी क्यों न हो इसमें कोई सन्देह नहीं किया कि यह राज्य अन्य राज्यों के समान विलय हो जायेगा और सावधानी से तैयार किये गये और प्रजातांत्रिक आधार पर खड़े भारतीय संविधान को स्वीकार करेगा। अतः जम्मू और काश्मीर के पक्ष में संविधान में दी

गई किसी अल्पकालीन विशेष धारा के आधार पर भारतीय संविधान को स्वीकार न किए जाने के औचित्य को सिद्ध करना बच्चों की सी बात है। यह विचार बल पकड़ रहा है कि हमारे ही रक्त तथा धन से हम शेख अब्दुल्ला और उसके अनुयायियों के लिए एक लगभग स्वतन्त्र राज्य निर्माण कर रहे हैं। जम्मू तथा लद्दाख की जनता ने पूर्ण विलय के पक्ष में अपनी घोषणा कर दी है। यदि काश्मीर घाटी के लोग भिन्न मत रखते हैं तो इस क्षेत्र के लिए अन्य कुछ विशेष उपबन्ध इस समय के लिए रह सकते हैं। हमें यह भी प्रायः बताया जाता है कि यदि भारतीय संविधान को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने के लिए कोई अनुचित दबाव दिया गया तो काश्मीर घाटी के मुसलमानों की भारत से पृथक हो जाने की संभावना है। यह तर्क बिलकुल भी समझ में नहीं आता। यदि हमारा संविधान ऐसा बना होता जिससे मुसलमानों को अपने भविष्य के विषय में घबराहट होती अथवा उन्हें समानता का बर्ताव न मिलने की संभावना होती, तो शायद इस तर्क में कुछ जान दिखाई देती। किन्तु अब ऐसा नहीं है, फिर इस झिझक का कारण क्या हो सकता है? श्री जिन्ना की पाकिस्तान की विचारधारा का भी यही आधार था कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश कभी भी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो हिन्दू बहुसंख्या वाली संसद से समर्थित केन्द्रीय सरकार को व्यापक शक्ति देता हो। काश्मीर के संबंध में इस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहन देना घोर सांप्रदायिक तथा प्रतिगामी कृत्य होगा। यह सब कुछ होते हुए भी, जैसाकि मैंने कहा, हम शेख अब्दुल्ला की राजधानी काश्मीर घाटी को किसी भी विशेष ढंग से जितने समय के लिए वे चाहें रखने को तैयार हैं, किंतु जम्मू और लद्दाख तो वहां की जनता की इच्छा के अनुसार पूर्णतः भारत में मिल जाने चाहिए। मैं इस बात को पुनः दुहराता हूं और स्पष्ट शब्दों में रखता हूं कि मैं जम्मू तथा काश्मीर का विभाजन नहीं चाहता। किंतु यदि शेख अब्दुल्ला अड़े हुए हैं तो जम्मू तथा लद्दाख का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए। काश्मीर घाटी को भारतीय संघ के अन्तर्गत एक पृथक राज्य बनाया जा सकता है जिसे सब आवश्यक सहायता प्राप्त हो और वैधानिक रीति से उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा शेख अब्दुल्ला और उनके सलाहकार चाहते हैं।

प्रजा परिषद् का आन्दोलन

प्रजा परिषद् के द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन को अत्यधिक और जानबूझ कर गलत ढंग से रखा गया है। यह केवल दुर्भाग्य का विषय है कि जब जम्मू की जनता अपने आपको भारत के साथ जिसे वह अपनी पवित्र भूमि मानती है, एक रूप करना चाहती हो- जब भारत सरकार न केवल उसके स्वप्न की पूर्ति में बाधक ही हो वरन् उन्हें प्रतिगामी, देशद्रोही, यहां तक कि पाकिस्तान का मित्र कहकर पुकारे। क्या केवल धर्मनिरपेक्षता के विकृत विचार और शेख अब्दुल्ला और उसके मित्रों द्वारा प्रस्तुत मांगों के आगे समर्पण के कारण किसी की दृष्टि इससे भी और अधिक धुंधली हो सकती है? श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों ने सम्मिलित रूप से जम्मू में भयंकर दमन की नीति अखत्यार की है। किन्तु मैं इस बात की असंदिग्ध रूप से घोषणा करता हूं कि दमन से यह समस्या हल नहीं होगी। जितना अधिक दमन होगा उतने ही घातक परिणाम होंगे। क्या श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला इस बात को नहीं जानते कि दमन से स्वयं उनके आन्दोलन नष्ट नहीं हुए थे? यही नहीं, इससे उन्हें भारी लाभ हुआ था। विलम्ब होने पर भी मैं श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला से निवेदन करूंगा कि वे दमन की इस नीति को छोड़ें और झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़ें। उन्हें जम्मू के वर्तमान नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते का मार्ग निकालना चाहिए जो सभी के लिए उचित तथा न्यायसंगत हो। इस दिशा में पहले कदम के रूप में जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा यह स्वीकार करें कि राज्य अन्तिम तथा औपचारिक रूप से भारत के साथ मिल गया है। दूसरे, जम्मू-काश्मीर विधान सभा यह स्वीकार करें कि नागरिकता, मूलभूत अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र, वित्तीय एकीकरण एवं राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी भारतीय संविधान की धारायें उस राज्य पर भी लागू होती हैं। शेष के विषय में मेरा विश्वास है कि यदि पारस्परिक सद्भावना और समझदारी के बाद बातचीत चली तो एक सन्तोषजनक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। जम्मू में आज की हालत चलने देना पूर्णतः अवांछित है और यह भी नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला के हाथ में है कि वे जम्मू के जन-प्रतिनिधियों के सच्चे भय से दूर करें, जिससे सब मिलकर जम्मू-काश्मीर के एक तिहाई प्रदेश को मुक्त करने का उद्योग करें, जो भी हमारे राष्ट्रीय अपमान के रूप में पाकिस्तान के अधिकार में है। इस बीच में हमारी क्रियात्मक सहानुभूति जम्मू के उन सब लोगों के साथ है जो अधिकारियों के कोप की अग्नि को साहस से सह रहे हैं और एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कष्ट उठा रहे हैं।

पूर्वी बंगाल

पूर्वी बंगाल की स्थिति से चारों ओर एक बेचैनी और क्षोभ उत्पन्न हुआ है और सारे देश ने एक स्वर से यह मांग की है कि भारत सरकार पूर्वी बंगाल में बचे हुए लगभग एक करोड़ हिन्दुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रति अनुरोध करें और प्रभावशाली कदम उठायें। विभाजन का आधार ही यह था कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही में अल्पसंख्यक सुरक्षा तथा सम्मान के साथ रहते रहेंगे। भारत की सीमाओं में आज भी चार करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। जहां तक अन्य अल्पसंख्यकों का प्रश्न है उन्हें कभी भी भय नहीं था और वे सदा की भांति शांतिपूर्वक यहां रह रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिख अल्पसंख्यक नाम शेष हो चुके हैं। पूर्वी बंगाल से भी लगभग 40-50 लाख हिन्दू अभी तक निकाले जा चुके हैं। हिंदुओं को बाहर निकालने की यह क्रिया समय-समय पर होती है जिसके परिणामस्वरूप भारी अपमान तथा कष्ट लोगों को उठाना पड़ रहा है। पारपत्र प्रणाली का आरम्भ ही एक निश्चित योजना तथा हिंदू विरोधी द्वेषभाव लेकर हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि यदि पूर्वी बंगाल में शेष बचे 90 लाख हिन्दुओं को निकलकर भारत आना पड़ा तो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसके अतिरिक्त पुनः संस्थापन के लिए सरकार को जो भारी मात्रा में व्यय करना पड़ेगा वह अलग से। यदि अल्पसंख्यक वहां इसी तरह रहते रहे जैसे आज रह रहे हैं तो या तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा उनकी स्थिति एक दास की होगी। ■

क्रमशः

स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगः जिंदगी में वर्षों का इजाफा

सी.पी. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति

सदियों से भारत की एक अनूठी पहचान रही है। उसकी यह पहचान 'वसुधैव कुटुंबकम' – यानी पूरी दुनिया को एक इकाई और सभी जीव-जंतुओं को एक मानने - की महान सोच में निहित रही है। भारत के इस आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित योग एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। योग के मूल तत्वों में आसन (शारीरिक मुद्राएं), प्राणायाम (सांस लेने की तकनीकें) और ध्यान शामिल हैं। इन तत्वों का मेल शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाता है।

दिनांक 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया को रहने योग्य और स्थिर बनाने के उद्देश्य से लोगों की जीवनशैली में बदलाव लाने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि योग मन एवं शरीर, सोच एवं कर्म, संयम एवं संतुष्टि के बीच एकता, इंसान एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य और सेहत एवं कल्याण से संबंधित एक समग्र दृष्टिकोण का संगम है। माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर, 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने से संबंधित 174 से अधिक देशों के सम्मिलित प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्ष 2015 से दुनिया भर में लाखों लोग सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर एक साथ योग करते हैं और इस प्रकार हमारे प्राचीन ज्ञान को एक वैश्विक आंदोलन का रूप देते हैं।

इस वर्ष 21 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी जहां कोलकाता में योग दिवस की अगुवाई करेंगे, वहीं मैं इस समारोह में भाग लेने के लिए लद्दाख में रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से पिछले कई वर्षों से मैंने भी योग एवं पंचकर्म के नियमित अभ्यास के लाभों को महसूस किया है। इन दोनों को अक्सर एक-दूसरे से जुड़ी विधाएं (सिस्टर साइंसेज) कहा जाता है। इन्हीं बेहद समृद्ध करने वाले व्यक्तिगत अनुभवों ने मुझे योग और मानव कल्याण पर इसके गहरे प्रभाव के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित किया है।

योगः भारत की एक शाश्वत विरासत

माना जाता है कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कल्याण से संबंधित 'योग' के कालजयी अभ्यास की शुरुआत हमारी सभ्यता के उदय के साथ ही हुई थी। योग की परंपरा में भगवान शिव को जहां सबसे पहला योगी या 'आदि योगी' और सबसे पहला गुरु या 'आदि गुरु' माना जाता है, वहीं योग के सिद्धांतों को 'योग सूत्र' में व्यवस्थित रूप से संकलित के कारण महर्षि पतंजलि को 'शास्त्रीय योग का जनक' माना जाता है। महर्षि पतंजलि का तमिलनाडु के साथ गहरा आध्यात्मिक नाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी भौतिक जीव समाधि भी तिरुपत्तूर में स्थित है।

हमारे श्रद्धेय ऋषियों और मुनियों ने दुनिया को योग का अमूल्य खजाना दिया। वर्षों के ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक साधना के बाद इन ऋषियों और मुनियों ने एक ऐसी समग्र प्रणाली विकसित की जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने योग के तीन महान मार्गों की व्याख्या की है- ज्ञान योग, जो बुद्धि एवं ज्ञान का मार्ग है; कर्म योग, जो निःस्वार्थ सेवा एवं सही कर्म का मार्ग है; और भक्ति योग, जो शुद्ध प्रेम और भक्ति का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि ये तीनों मार्ग अंततः परम सत्य की अनुभूति में एकाकार हो जाते हैं।

आज योग भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं के बंधन से आगे निकल गया है। यह भारत के ऋषियों के शाश्वत ज्ञान और मानवता के कल्याण में उनके चिरस्थायी योगदान का जीवंत प्रमाण है।

स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग

हर वर्ष हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और एक सार्थक विषय के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष के विषय 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' का खास महत्व है। स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में हुई उल्लेखनीय प्रगति और मृत्यु दर में आई कमी के कारण दुनिया भर में लोगों की औसत आयु बढ़ी है। भारत भी आबादी में हो रहे इस बड़े बदलाव का साक्षी बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' के अनुसार, 2050 तक भारत में हर पांच में से लगभग एक व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी।

लंबी आयु के इस अनमोल उपहार का उत्सव मनाते हुए समाज पर यह सुनिश्चित करने की एक महती जिम्मेदारी भी है कि जिंदगी में मिले इन अतिरिक्त वर्षों का मतलब केवल आयु में बढ़ोतरी ही न हो, बल्कि उन वर्षों में जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो। इसी संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 का विषय – 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' - एक बहुत ही सामयिक संदेश के रूप में सामने आया है।

आबादी में आए इस बदलाव के कारण भारत में 'सिल्वर इकॉनमी'

का विस्तार हुआ है, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों से जुड़े सामानों एवं सेवाओं पर केंद्रित है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी इसका आकार लगभग 73,000 करोड़ रुपये का है। आने वाले वर्षों में इस सेक्टर के काफी बढ़ने की उम्मीद है।

आज के दौर में आयु बढ़ने से जुड़ी हकीकतों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि बुजुर्ग लोग कैसे विभिन्न प्रकार की मुश्किलों एवं कमजोरियों के जटिल जाल से जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दुनिया भर में बुजुर्गों के बीच गैर-संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और सामाजिक अलगाव के बढ़ते बोझ को बार-बार रेखांकित किया है।

मेरा भी यह मानना है कि आज वक्त की यह मांग है कि लोगों को कम आयु से ही योग से जोड़ा जाए। योग का अभ्यास जितनी जल्दी शुरू किया जाए, जीवन भर उसके उतने ही अधिक लाभ मिलते हैं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योग को स्वास्थ्य, कल्याण और मूल्यों पर आधारित शिक्षा के एक अहम हिस्से के तौर पर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। युवाओं को योग से जोड़ने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। इससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रकार, हम पाते हैं कि दुनिया भर में बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के बीच भारत दुनिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का एक अनूठा मॉडल प्रदान कर रहा है - एक ऐसा मॉडल जो प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठाता है - और वह है योग।

योग - आज के दौर में बुढ़ापे से जुड़ी समस्याओं का समाधान

आज, आधुनिक विज्ञान हमारे उन ऋषियों एवं योगियों की शाश्वत बातों की पुष्टि कर रहा है, जिन्होंने अनुशासित जीवन, योग और आध्यात्मिक साधना के जरिए असाधारण लंबी आयु, जीवन-शक्ति और मानसिक स्पष्टता हासिल की थी। हाल के वर्षों में योग के उपचारात्मक पहलुओं में अकादमिक और क्लिनिकल अभिरुचि तेजी से बढ़ी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (एनआईएच) एवं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसे बड़े संस्थानों और 'लैंसेट' जैसी कई प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं ने अपने शोधों में इस तथ्य को दर्शाया है कि नियमित रूप से योग करने से बुजुर्गों में संतुलन, लचीलापन और चलने-फिरने की क्षमता सुरक्षित रूप से बेहतर होती है। इससे उनके गिरने का डर और जोखिम काफी कम हो जाता है। शोधों से यह भी पता चला है कि योग से हड्डियों की मजबूती (बोन डेंसिटी) बढ़ती है, गठिया का दर्द कम होता है, सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है, रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) स्थिर रहता है और मानसिक सेहत अच्छी रहती है। साथ ही, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से बुजुर्गों की नींद की गुणवत्ता, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की मानसिक क्षमता और सोचने-समझने की शक्ति (कॉग्निटिव फंक्शनिंग) में भी सुधार देखा गया है।

लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि योग की असली ताकत उसके समग्र स्वरूप में निहित है। शारीरिक सुधार से कहीं आगे बढ़कर योग भावनात्मक संतुलन और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। मैंने देखा है कि आज बुजुर्गों के बीच अकेलेपन का बढ़ता अहसास एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। योग धीरे-धीरे इस अकेलेपन को सामूहिक जुड़ाव की भावना में बदल देता है। यह लोगों को "मैं-केंद्रित" सोच से हटाकर सहानुभूति, आपसी जुड़ाव एवं आंतरिक शांति पर आधारित 'हम-केंद्रित' सोच की ओर ले जाता है।

मेरे अपने अनुभव के अनुसार, अहम बात यह है कि 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' में बहुत अधिक शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं होती। पारंपरिक योग क्रियाओं को काफी सोच-समझकर ऐसे सरल एवं सुलभ तरीकों में ढाला गया है जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हैं। इनमें योगिक सूक्ष्म व्यायाम (जोड़ों की हल्की हरकतें), कुर्सी की मदद से किए जाने वाले आसन, सांस लेने की निर्देशित तकनीकें और ध्यान जैसी क्रियाएं शामिल हैं। ये सब बढ़ती आयु के शरीर पर बिना कोई दबाव डाले न्यूरोएंडोक्राइन प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

साथ ही, योग उन देखभाल करने वालों और परिवार के सदस्यों के लिए भी हौसले एवं सहनशक्ति का स्रोत है, जो बुजुर्गों की देखभाल की भावनात्मक तथा शारीरिक जिम्मेदारियां उठाते हैं। इन व्यापक लाभों को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने 'गैर-संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए योग की 10 विधाओं' से जुड़ी एक अहम पहल शुरू की है। इसमें बुजुर्गों की सेहत के लिए खास तौर पर साक्ष्यों पर आधारित योग मॉड्यूल भी शामिल है। इसके अलावा, 100 दिनों का मुफ्त निर्देशित ऑनलाइन योग कार्यक्रम प्रदान करने वाले 'योग 365' पहल नाम के एक देशव्यापी अभियान को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है ताकि योग सभी आयु के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक सहज एवं स्थायी साथी बन सके।

दो हजार से भी अधिक वर्ष पहले महान तमिल विद्वान एवं संत तिरुवल्लुवर ने 'कुरल' (949) के जरिए सेहत से संबंधित एक व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण की हिमायत की थी। उन्होंने कहा था, "उपचार शुरू करने से पहले मरीज की हालत, बीमारी की प्रकृति और उपयुक्त समय पर विचार करें।" यह शाश्वत समझ स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाती है, जहां व्यक्ति की उम्र, सेहत और जरूरतों के हिसाब से अभ्यास को सावधानी से अपनाया जाता है ताकि लोग बुढ़ापे में भी अधिक स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जी पाएं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर मैं हर नागरिक, शिक्षण संस्थान, नागरिक समाज संगठन, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवर और समुदायों के नेता से आग्रह करता हूं कि वे योग को केवल कभी-कभार की जाने वाली कसरत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली सांस्कृतिक एवं सेहत से जुड़ी एक आदत के तौर पर अपनाएं। किसी समाज की असल पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल रखता है। इसलिए, आइए हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें जहां हमारे बुजुर्ग डर, निर्भरता या अकेलेपन के बीच नहीं, बल्कि सम्मान, जोश, सार्थक उद्देश्य और शांति के साथ जीवन जी सकें। योग को जीवन का एक लय बनाकर, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे नागरिकों के जीवन के सुनहरे वर्ष सचमुच सेहत, सामंजस्य और संतुष्टि से भरे हों! ■

फसल से आगे, समृद्धि की ओर

शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण
तथा ग्रामीण विकास मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो, किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शिता और किसान-हितैषी नीतियों ने कृषि को सिर्फ 'उत्पादन का क्षेत्र' नहीं रहने दिया, बल्कि किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बना दिया है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियों का फोकस केवल 'कितना उत्पादन' पर नहीं, बल्कि 'किसान की वास्तविक आय कितनी, खेती कितनी टिकाऊ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मज़बूत' पर आ गया है। इसी सोच से दलहन–तिलहन मिशन, कॉटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध–नवाचार; सबको एक ही व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है।

उत्पादन से आगे : आय, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम-सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने देशभर में करोड़ों किसान-आवेदनों को कवर करते हुए फसल के नुकसान की स्थिति में एक मज़बूत बीमा कवच दिया है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि-अवसंरचना, वेयरहाउस और कोल्ड-चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाज़ार तक पहुंच- तीनों को मजबूत किया है। कृषि अब सिर्फ खेत की मेड़ तक सीमित नहीं है। डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट, बागवानी, मधुमक्खी-पालन, खाद्य-प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रामीण उद्योग, सौर ऊर्जा और सेवा-क्षेत्र; सब मिलकर नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

दलहन, तिलहन और कॉटन मिशन : आत्मनिर्भरता और मूल्य–सुरक्षा

लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपास– तीनों क्षेत्र हमारी पूरी क्षमता से पीछे रहे। हम दालों और तेलों के लिए आयात पर निर्भर रहे और कपास में भी किसानों को वैश्विक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय दलहन मिशन के माध्यम से तुअर, उड़द, मसूर, चना और अन्य दालों का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाज़ार तक पूरी वैल्यू चेन पर काम हो रहा है– उच्च-उपज किस्में, क्लस्टर आधारित खेती, प्रसंस्करण इकाइयां, MSP का सुदृढ़ ढांचा, सरकारी खरीद, भंडारण और निर्यात तक। लक्ष्य यह है कि भारत दालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने, आयात बिल घटे और किसानों को उच्च मूल्य वाली इन फसलों से स्थायी आय मिले। इसी तरह तिलहन मिशन के ज़रिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और

आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम-सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने देशभर में करोड़ों किसान-आवेदनों को कवर करते हुए फसल के नुकसान की स्थिति में एक मज़बूत बीमा कवच दिया है

पाम ऑयल जैसी फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह केवल पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, किसानों को बेहतर दाम और देश की तेल सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में व्यापक रणनीति है। इसके साथ-साथ कॉटन मिशन के तहत कपास की उच्च-उपज और कीट-रोधी किस्में, उन्नत कृषि-प्रणालियां, कीट-प्रबंधन, फसल विविधीकरण, टेक्सटाइल वैल्यू–चेन से बेहतर जुड़ाव और गुणवत्ता सुधार पर काम हो रहा है। कपास भारत के लाखों किसानों के लिए नकदी फसल है; मिशन का उद्देश्य है कि किसान को उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके।

प्राकृतिक खेती मिशन : 1 करोड़ किसान, 75 लाख हेक्टेयर की नई राह

तेज़ी से बढ़ती रासायनिक निर्भरता, मिट्टी की थकान और भूजल पर दबाव– ये सब हमें आगाह कर रहे हैं कि खेती के तरीके बदलने होंगे। इसी समझ के साथ हमारे विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज़ किया जाए, उनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए।

यह परिवर्तन धीरे-धीरे, वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहा है। छोटे किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाकर देखें; उन्हें प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधनों पर आधारित पैकेज, प्रमाणन, ब्रांडिंग और बाज़ार-जुड़ाव में मदद दी जा रही है। उद्देश्य यह है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े, रासायनिक लागत घटे, जलवायु झटकों के सामने फसलें अधिक टिकाऊ हों और उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद, पोषक भोजन मिल सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने 2014–25 के बीच लगभग 3,000 जलवायु-सहनशील फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें सूखा, बाढ़, लू, लवणीयता और अन्य तनावों को झेलने की क्षमता है। कुल मिलाकर 3,800 से ज़्यादा उच्च-उपज किस्में और 200 से अधिक बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं, जो उत्पादकता के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी मजबूत करती हैं

प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना और फोकस में 100 कम उत्पादन वाले ज़िले

भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ ज़िले अलग-अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले ज़िलों की पहचान की गई है, जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन ज़िलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं का कन्वर्जेन्स कर एक समग्र पैकेज दिया जा रहा है– सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि–उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाज़ार-जुड़ाव; सबको एक साथ जोड़कर। सोच यह है कि योजनाएं अलग-अलग 'साइलो' में न चलें, बल्कि किसान के खेत और गांव को केंद्र में रखकर सब मिलकर काम करें। इससे नीति का फोकस केवल 'कितना उत्पादन' से आगे बढ़कर इस पर आया है कि कहां उत्पादन कम है, वहां लक्षित निवेश और प्रयास से कैसे बढ़ाया जाए, और उससे किसान की आय कैसे ऊपर उठे।

'खेत बचाओ अभियान' : मिट्टी, पानी और किसान का संतुलन

उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में कई जगहों पर मिट्टी और पानी पर दबाव बढ़ा है। असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन और सीमित फसल चक्र ने खेत की सेहत को प्रभावित किया है। यदि समय रहते दिशा न बदली जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कमजोर खेत और थकी हुई मिट्टी छोड़ेंगे। इस चुनौती को देखते हुए 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया गया है। यह अभियान केवल मिट्टी बचाने का नहीं, बल्कि किसान की आय, भोजन की गुणवत्ता और भविष्य की खाद्य सुरक्षा की रक्षा का अभियान है। इसके पांच मुख्य संदेश हैं- हर किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करे, डीएपी और यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करे और संतुलित NPK, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव एवं नैनो उर्वरकों को अपनाए, हरी खाद, जैविक खाद और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के विरुद्ध सतर्क रहे और प्रशासन को तुरंत सूचना दे तथा प्राकृतिक खेती और जलवायु–अनुकूल पद्धतियों की ओर संगठित रूप से बढ़े। लक्ष्य यह नहीं कि उर्वरक अचानक कम कर दिए जाएं, बल्कि यह है कि हर किसान सही मात्रा, सही समय और सही मिश्रण का उपयोग करे, ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहे, लागत घटे और उत्पादन भी सुरक्षित रहे।

विज्ञान, डिजिटल कृषि और ICAR की भूमिका

इन सभी प्रयासों की रीढ़ विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने 2014–25 के बीच लगभग

3,000 जलवायु-सहनशील फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें सूखा, बाढ़, लू, लवणीयता और अन्य तनावों को झेलने की क्षमता है। कुल मिलाकर 3,800 से ज़्यादा उच्च-उपज किस्में और 200 से अधिक बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं, जो उत्पादकता के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी मजबूत करती हैं। डिजिटल कृषि मिशन और 'एग्रीस्टैक' के तहत किसान पहचान (Farmer IDs), फसल प्लॉटों का डिजिटलीकरण, ड्रोन-आधारित सेवाएं, कीट-रोग निगरानी, मौसम–आधारित और लोकेशन–स्पेसिफिक सलाह जैसी व्यवस्थाएं बन रही हैं। इससे लैब से लैंड और डेटा से निर्णय तक की दूरी तेजी से कम हो रही है। ई-नाम, किसान सारथी, KVK नेटवर्क, मोबाइल संदेश, व्हाट्सऐप समूह, सामुदायिक रेडियो और सोशल मीडिया– इन सबके माध्यम से वैज्ञानिक, विस्तारकर्मी और किसान–नेता सीधे किसान से संवाद कर पा रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास को भी एक साथ, समग्र दृष्टि से देखा जा रहा है। सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्व-सहायता समूह, FPO, ग्रामीण उद्योग और कौशल विकास– ये सभी कार्यक्रम जब कृषि के साथ कदम–ताल करके चलते हैं, तभी गांवों में रोज़गार, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ती है।

फसल की मात्रा से आगे, किसान के विश्वास की ओर बढ़ते ठोस कदम

आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की खाद्य, पोषण और जलवायु चुनौतियों के बीच अपने कृषि-तंत्र को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विज़न स्पष्ट है- किसान की आय बढ़े, उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिले, दालों, तिलहनों और कपास में आत्मनिर्भरता से पोषण, तेल और वस्त्र सुरक्षा मजबूत हो। PM-KISAN, PMFBY, प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ अभियान और जलवायु-अनुकूल तकनीकों से खेत की मिट्टी, पानी और किसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले ज़िलों में लक्षित निवेश से क्षेत्रीय असमानता घटे और हर किसान आगे बढ़े। विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक से खेती कुशल, लचीली, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बने।

जब खेत बचेगा, तब किसान बचेगा। जब किसान बचेगा, तब कृषि बचेगी और जब कृषि बचेगी, तब भारत का भविष्य सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में यही हमारी नई कृषि यात्रा का सार है– फसल से आगे, किसान के विश्वास और ग्रामीण भारत की समृद्धि की ओर। ■

अभिनंदन! अभिनंदन!! अभिनंदन!!!

राज्यसभा चुनाव-2026 में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में अपनी संगठनात्मक क्षमता और विधानसभाओं में बढ़ी शक्ति के बल पर शानदार सफलता प्राप्त की। देश भर के अलग-अलग राज्यों से कई नए सदस्यों के चुने जाने से राज्यसभा में भाजपा की उपस्थिति और सशक्त हुई। ये सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यापक राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक विशेषज्ञता और जनसेवा के अनुभव से संपन्न हैं। नवनिर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं-

राज्य	नाम	अवधि
अरुणाचल प्रदेश	श्री ताई तागाक	24/06/2026 से 23/06/2032
गुजरात	श्री राजूभाई शुक्ला	22/06/2026 से 21/06/2032
	श्री मुकेशभाई राठवा	22/06/2026 से 21/06/2032
	श्री मानसिंह परमार	22/06/2026 से 21/06/2032
	श्री जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया	22/06/2026 से 21/06/2032
मध्य प्रदेश	श्री तरुण चुग	22/06/2026 से 21/06/2032
	श्री रजनीश अग्रवाल	22/06/2026 से 21/06/2032
	श्री महेश केवट	22/06/2026 से 21/06/2032
मणिपुर	श्रीमती ए. शारदा देवी	22/06/2026 से 21/06/2032
राजस्थान	श्रीमती (डॉ.) अलका गुर्जर	22/06/2026 से 21/06/2032
	डॉ. सतीश पूनिया	22/06/2026 से 21/06/2032
ओडिशा	श्री देबाशीष सामंतराय	11/06/2026 से 03/04/2030
कर्नाटक	प्रो. (डॉ.) एम. नागराज	12/06/2026 से 11/06/2032

भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण

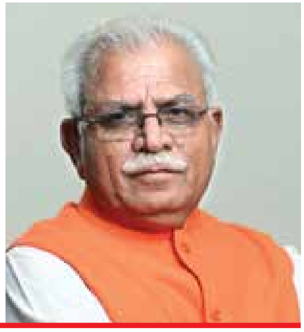

मनोहर लाल

केंद्रीय आवास और शहरी कार्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का लक्ष्य 'ग्लोबल साउथ' को सुरक्षित, मजबूत, निष्पक्ष और स्थाई वैश्विक ऊर्जा प्रदान करना है।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। देश आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और जलवायु-संबंधी बाधाओं का सामना करने की क्षमता भी विकसित कर रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है, जिससे सहयोग और नवाचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ काम करने, समाधान साझा करने और अधिक मज़बूत एवं टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने का अवसर प्रदान करता है।

भारत "लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी का निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) थीम के तहत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऊर्जा का क्षेत्र इस थीम को सबसे बेहतर ढंग से दिखाता है। ऊर्जा वह आधार है जिस पर देश की हर दूसरी महत्वाकांक्षा टिकी है — चाहे वह आर्थिक विकास हो, रोज़गार पैदा करना हो, शिक्षा, खेती या डिजिटल अर्थव्यवस्था हो। जब विभिन्न राष्ट्रों के ऊर्जा मंत्री और लगभग दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि दिल्ली में इकट्ठा हुए, तो यह शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में भारत की भूमिका पर विचार करने का सही समय है।

भारत ने अपनी प्रमुख 'सौभाग्य योजना' के तहत रिकॉर्ड 2.86 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाकर सभी के लिए बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हर घर तक बिजली पहुंचने से प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 1,450 यूनिट हो गई है, जो 2013-14 के स्तर से 52 प्रतिशत अधिक है। अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2030 तक लगभग 2,000 यूनिट और 2047 तक लगभग 4,000 यूनिट हो जाएगी, जो बढ़ती खुशहाली और बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है

इस ऊर्जा प्रणाली की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री ने तब तैयार की थी जब उन्होंने कॉप—26 में 2070 तक नेट ज़ीरो बनने के भारत के संकल्प की घोषणा की थी। "सभी के लिए ऊर्जा" (Energy for All) वह ढांचा है जो ब्रिक्स देशों की साझा प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस ढांचे के मुख्य स्तंभ ये हैं:

- ऊर्जा तक पहुंच और समानता
- ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी
- टेक्नोलॉजी और नवाचार
- ऊर्जा तक पहुंच

भारत ने अपनी प्रमुख 'सौभाग्य योजना' के तहत रिकॉर्ड 2.86 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाकर सभी के लिए बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हर घर तक बिजली पहुंचने से प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 1,450 यूनिट हो गई है, जो 2013-14 के स्तर से 52 प्रतिशत अधिक है। अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2030 तक लगभग 2,000 यूनिट और 2047 तक लगभग 4,000 यूनिट हो जाएगी, जो बढ़ती खुशहाली और बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है।

भारत ने पिछले 12 सालों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 540 गिगावॉट से अधिक कर लिया है। इस तेज़ी से हुई बढ़ोतरी की वजह से ही हम मौजूदा गर्मी के मौसम में 270.8 गिगावॉट की अब तक की सबसे ज़्यादा पीक डिमांड को पूरा कर पाए हैं।

खास बात यह है कि भारत ने नॉन-फॉसिल फ्यूल स्रोतों से अपनी इंस्टॉल्ड बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है, जो उसके 'नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन' कमिटमेंट से पांच साल से भी पहले हुआ है। यह भारत की उस क्षमता को दिखाता है जिसके माध्यम से वह बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने क्लाइमेट लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए भारत अब अपने ऊर्जा बदलाव के अगले चरण

की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि 2035-36 तक बिजली की पीक डिमांड लगभग 459 गिगावॉट तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए लगभग 1,121 गिगावॉट की इंस्टॉल्ड क्षमता की आवश्यकता होगी। इस विस्तार में मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड एनर्जी की बड़ी भूमिका होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अपनी 'कोइन्सिडेंट पीक ऑब्लिगेशन्स' के हिसाब से लंबी अवधि की योजना बनानी होगी और उसे हासिल करना होगा। यह भारत के पावर सेक्टर में एक अहम बदलाव है, जो हमारे बिजली सिस्टम की बढ़ती परिपक्वता, आधुनिकता और मजबूती को दर्शाता है।

मौजूदा जियोपॉलिटिक्स (भू-राजनीति) के कारण एनर्जी सिक्योरिटी (ऊर्जा सुरक्षा) का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। भारत बिजली पर केंद्रित एक विविध एनर्जी बास्केट बनाने का प्रयास कर रहा है। कोयले का अच्छा भंडार होने के कारण हमने पहले ही थर्मल पावर प्लांट में आयातित कोयले की ब्लेंडिंग (मिश्रण) कम कर दी है और आयातित कोयले पर चलने वाले प्लांट में घरेलू कोयले की ब्लेंडिंग की संभावना तलाश रहे हैं। बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीफिकेशन एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसी के तहत 'नेशनल कोल गैसीफिकेशन मिशन' शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन का उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन और उससे बनने वाले उत्पाद भी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहे हैं - न केवल घरेलू आवश्यकताओं के लिए, बल्कि निर्यात के एक बड़े साधन के तौर पर भी। सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

भारत बिजली पर केंद्रित एक विविध एनर्जी बास्केट बनाने का प्रयास कर रहा है। कोयले का अच्छा भंडार होने के कारण हमने पहले ही थर्मल पावर प्लांट में आयातित कोयले की ब्लेंडिंग (मिश्रण) कम कर दी है और आयातित कोयले पर चलने वाले प्लांट में घरेलू कोयले की ब्लेंडिंग की संभावना तलाश रहे हैं। बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीफिकेशन एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसी के तहत 'नेशनल कोल गैसीफिकेशन मिशन' शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन का उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन और उससे बनने वाले उत्पाद भी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहे हैं - न केवल घरेलू आवश्यकताओं के लिए, बल्कि निर्यात के एक बड़े साधन के तौर पर भी। सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है

सौर ऊर्जा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) ट्रांज़िशन का मुख्य आधार है। हमारी सौर ऊर्जा क्षमता, जो अभी 157 गिगावॉट है, 2014-15 की तुलना में 54 गुना बढ़ गई है और अगले दशक में इसके 500 गिगावॉट से अधिक होने का अनुमान है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के इस बड़े विस्तार में ट्रांसमिशन सेक्टर एक ऐसा हीरो है जिसकी चर्चा कम ही होती है। पिछले दशक में ट्रांसमिशन नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनाइज़्ड ग्रिड में से एक बन गया है, जो कम-कार्बन वाले बदलाव के लिए आवश्यक क्षमता और लचीलापन देता है।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन

डिजिटल इनोवेशन भविष्य के पावर सिस्टम को तेज़ी से आकार दे रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है; अब तक 6 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे ग्रिड स्मार्ट हो गया है और समय या उपयोग के आधार पर दरें तय करना मुमकिन हो गया है।

भविष्य के इंटेलिजेंट और कनेक्टेड सिस्टम उतनी ही वैल्यू पैदा करेंगे जितनी आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। अब हर ग्राहक के पास प्रोड्यूसर बनने का मौका है।

पीएम सूर्य घर योजना पहले ही 40 लाख घरों में इंस्टॉलेशन के साथ अपनी जगह बना रही है और यह पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रांज़ेक्शन का रास्ता खोलेगी।

इंडिया एनर्जी स्टैक इस बदलाव को आसान बनाने के लिए भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। पावर सेक्टर के लिए यूपीआई जैसा क्रांतिकारी दौर आने वाला है।

कंज्यूमर-सेंट्रिक एनर्जी सिस्टम की ओर इस बदलाव का अगला चरण विकेंद्रीकरण है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं; एटीएंडसी नुकसान घटकर 15 प्रतिशत हो गया है और यूटिलिटी कंपनियां पहली बार पेट पॉजिटिव हुई हैं।

भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि मजबूत एनर्जी सिस्टम न केवल मजबूत घरेलू नीतियों से, बल्कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से भी बनते हैं।

ब्रिक्स की असली ताकत एक-दूसरे की खूबियों और आवश्यकताओं को पूरा करने में है। ब्रिक्स के किसी एक देश के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन साथ मिलकर हमारे पास सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ एनर्जी सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी लगभग हर वस्तु उपलब्ध है।

इस साल ब्रिक्स की अगुवाई करते हुए हमारी कोशिश है कि इस साझा सोच को ठोस नतीजों में बदला जाए और एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण किया जाए। ■

जन विश्वास से सुगम होता जीवन

सुधारों की प्रक्रिया के पीछे प्रधानमंत्री का यही दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक काल के तौर-तरीकों से पूरी नहीं होंगी

पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

भारत की नियामकीय प्रणाली हमेशा दुविधा की मानसिकता के साथ काम करती थी और अक्सर छोटी प्रक्रियागत त्रुटियों या केवल आरोपों के कारण नागरिकों को कड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ते थे। मोदी सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए विश्वास, सहानुभूति और सम्मान में निहित शासन को बढ़ावा देते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ घटाना हो, डिजिटलीकरण बढ़ाना हो, या एकल-खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना रहा है।

प्रधानमंत्री का विश्वास और सहानुभूति पर आधारित शासन का मंत्र स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है। नागरिक-अनुकूल नियामकीय परिवेश बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता है: दंड से पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित एवं पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे। यह दृष्टिकोण, अनुपालन और प्रवर्तन के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं।

इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रविधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 717 प्रविधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रविधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है। यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है। पुराने अप्रचलित अपराधों को समाप्त कर आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है। पूर्व की व्यवस्था में किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच उपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब न देने पर किसी व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल हो सकती थी। औपनिवेशिक काल में सामान्य आवाजाही की संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले इस प्रविधान को समाप्त कर दिया गया है। पहले किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। नए कानून में इस मोर्चे पर 30 दिन की छूट अवधि दी गई है। इसी क्रम में अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन न कर पाना पहले आपराधिक कृत्य था, पर अब केवल नियमों की बार-बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई होगी। पहले किसी खनन कंपनी की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में चूक के कारण जेल तक हो सकती थी, लेकिन अब जुर्माना ही पर्याप्त है।

इस संदर्भ में जन विश्वास कानून वस्तुतः समस्त नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के पीएम मोदी के प्रयासों का ही प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर देश-सेवा के 12 वर्षों में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका प्रमुख मिशन रहा है। जन विश्वास, 2026 एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है। भारत ने 2023 में पहले जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183

जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रविधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 717 प्रविधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रविधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है। यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है। पुराने अप्रचलित अपराधों को समाप्त कर आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है

प्रविधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर किए बिना गैर-अपराधीकरण से शासन में सुधार संभव है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ाता है, जो यह संकेत है कि यह कोई एक बार की गई पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समग्रता में देखें तो कम गंभीरता वाले आपराधिक प्रविधानों की जगह प्रशासनिक और मौद्रिक व्यवस्थाएं लाना, न सिर्फ आम नागरिक के लिए स्वागतयोग्य है, बल्कि छोटे व्यवसायों की भी मदद करता है। इससे प्रवर्तन एजेंसियां भी रोजमर्रा की तकनीकी गलतियों के बजाय गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

वर्षों तक मामूली गलतियों के लिए कानूनी शिकंजे का डर निवेश की राह में बड़ा अवरोध बना हुआ था, लेकिन अब नियमों को सुगम बनाने का परिणाम निवेश रुझानों में स्पष्ट दिखता है। देश में 2014 से 2025 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सिलसिला निरंतर तेज हो रहा है। स्पष्ट है कि इन कदमों का उद्देश्य भारत को निवेश और कारोबार के लिए अधिक भरोसेमंद और स्थायित्व से परिपूर्ण गंतव्य बनाकर इस रुझान को और गति प्रदान करना है

वहीं, अदालतें उन मामलों पर ध्यान दे सकती हैं, जिनमें सचमुच न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नियमों में सुगमता के लाभ अर्थव्यवस्था और निवेश के मोर्चे पर भी मिलते हैं। तेजी से प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नियमों की विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। वर्षों तक मामूली गलतियों के लिए कानूनी शिकंजे का डर निवेश की राह में बड़ा अवरोध बना हुआ था, लेकिन अब नियमों को सुगम बनाने का परिणाम निवेश रुझानों में स्पष्ट दिखता है। देश में 2014 से 2025 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सिलसिला निरंतर तेज हो रहा है। स्पष्ट है कि इन कदमों का उद्देश्य भारत को निवेश और कारोबार के लिए अधिक भरोसेमंद और स्थायित्व से परिपूर्ण गंतव्य बनाकर इस रुझान को और गति प्रदान करना है।

ऐसे सुधारों से न्यायिक प्रणाली को भी राहत मिलेगी। देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 5.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं और इनमें एक बड़ी संख्या छोटे-मोटे उल्लंघनों की है, जिन्हें अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों को प्रशासनिक निर्णय के लिए भेजना सिर्फ एक कारोबारी सुधार नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार भी है। इससे अदालतों को अपने सीमित समय और संसाधनों को गंभीर विवादों और न्याय से जुड़े अहम सवालों पर केंद्रित करने का मौका मिलता है। इस बीच यह न भूला जाए कि गंभीर उल्लंघनों के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहां सख्ती जरूरी है, वहां कानून पूरी तरह सख्त बना रहेगा। बदलाव सिर्फ दृष्टिकोण में आया है। शासन अब संदेह से विश्वास, अभियोजन से सुधार और भय से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। ■

लोकतंत्र अमर रहे

स्वतंत्रता को याद रखना क्यों आवश्यक है

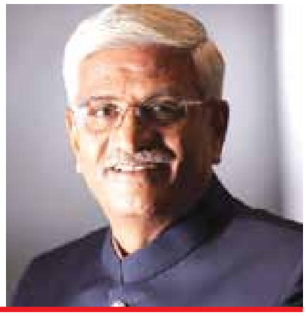

गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री

आपातकाल लागू हुए पचास साल हो चुके हैं और देश आज भी उस दौर पर विचार कर रहा है जिसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। 'संविधान हत्या दिवसः लोकतंत्र अमर रहे' के राष्ट्रीय आयोजन के समापन समारोह का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उन स्थायी मूल्यों पर चिंतन करना भी है जो हमारे गणतंत्र को बनाए रखते हैं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने एक बार कहा था: "संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है; यह जीवन का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा उस दौर की भावना होती है।"

बहुत कम बातें हमारे संवैधानिक यात्रा के सार को इन शब्दों से अधिक प्रभावशाली ढंग से बयां करती हैं। संविधान केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है जो राज्य के कामकाज को नियंत्रित करता है। यह नागरिकों और संस्थाओं, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों तथा आजादी और जवाबदेही के बीच एक जीवंत समझौता है।

लोकतंत्र को बचाए रखना अवश्यक है

भारत की लोकतांत्रिक भावना हमारी सभ्यता की परंपराओं में गहराई से बसी है। सदियों से हमारे समाज ने सलाह-मशविरे, सामूहिक विचार-विमर्श और जन-भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा दिया है। यह याद रखना आवश्यक है कि भारत को लोकतंत्र विरासत में नहीं मिला; उसने इसे खुद विकसित किया है। प्राचीन सभाओं और समितियों से लेकर आज़ादी के बाद की संसदीय प्रणाली तक हमने हमेशा लोगों की सामूहिक इच्छा में विश्वास किया है।

संविधान ने इन परंपराओं को एक आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में बदल दिया, साथ ही उन मूल्यों को भी बचाए रखा जिन्होंने पीढ़ियों से इन्हें बनाए रखा था। संविधान की प्रस्तावना हमारी संवैधानिक दिशा-सूचक है— न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।

ये केवल संवैधानिक आदर्श नहीं हैं। ये राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं। ये सार्वजनिक नीति का मार्गदर्शन करती हैं, संस्थाओं को आकार देती हैं और राज्य तथा नागरिक के बीच के रिश्ते को तय करती हैं। साथ ही, इतिहास हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।

1975-77 का आपातकाल आज़ाद भारत के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। इसने दिखाया कि जब संवैधानिक सुरक्षा-उपाय कमज़ोर पड़ जाते हैं और लोगों की आज़ादी पर रोक लगाई जाती है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कितना दबाव पड़ सकता है। उस दौर का असर केवल राजनीतिक जीवन तक ही सीमित नहीं था। इसने देश भर के नागरिकों के रोज़मर्रा के जीवन को भी प्रभावित किया।

इसकी भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि संवैधानिक अधिकार केवल कागज़ी कानूनी सिद्धांत नहीं हैं; ये ऐसे सुरक्षा-कवच हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की गरिमा, आज़ादी और रोज़मर्रा के जीवन को आकार देते हैं। जब इन अधिकारों में कटौती की जाती है, तो केवल संस्थाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आम लोगों, परिवारों और समुदायों की आज़ादी और आकांक्षाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। फिर भी, उस दौर से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वह है लोकतंत्र की मजबूती और मुश्किलों से उबरने की क्षमता।

भारत के लोगों ने संवैधानिक तरीकों में असाधारण भरोसा दिखाया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने आखिरकार लोकतांत्रिक कमियों को ठीक किया। शांतिपूर्ण भागीदारी और वोटिंग के माध्यम से नागरिकों ने इस सिद्धांत को फिर से साबित किया कि सत्ता जनता के हाथ में होती है। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है— सीखने, ढलने, खुद को सुधारने और मुश्किल समय से और मज़बूत होकर उभरने की इसकी क्षमता।

इस अवसर पर एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे मुश्किल दौर में से एक की एक विज़ुअल यात्रा की तरह है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड, विरोध की कहानियां, संवैधानिक पड़ाव और आपातकाल के दौरान लोगों के अनुभव दिखाए गए हैं।

इस मौके का एक और अहम हिस्सा पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री राम बहादुर राय का एक खास मेमोरियल

लेक्चर है— जो संवैधानिक सतर्कता और लोकतांत्रिक सुधार के बड़े विषय को आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाता है।

आज के समय में आज़ादी के लगभग आठ दशक बाद भी लोकतंत्र का मतलब लगातार बदल रहा है। नागरिक अब केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि भागीदारी भी चाहते हैं; केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि जवाबदेह शासन भी चाहते हैं। वित्तीय समावेश, ज़मीनी स्तर पर भागीदारी और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने वाली पहलों ने लोकतंत्र की पहुंच को बढ़ाया है।

साथ ही, नागरिकता की ज़िम्मेदारी और भी अहम हो गई है। एक मजबूत लोकतंत्र जागरूक नागरिकों पर निर्भर करता है। आज, जब दुनिया भारत की ओर देखती है और उसे 'लोकतंत्र की जननी' कहती है, तो यह हमारी लंबी सभ्यतागत यात्रा की पहचान है— प्राचीन राजाओं के धर्म से लेकर आधुनिक वोटरों की इच्छा तक।

आज़ादी के जीवंत नायक

यह समापन समारोह कार्यक्रम लोकतंत्र की उस व्यापक समझ को दिखाता हैं, जिसके तहत लोकतंत्र एक जीवंत और लगातार विकसित होने वाले राष्ट्रीय अनुभव बन जाता है।

डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपॉजिटरी पर लगी प्रदर्शनी— जो 2021 में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू की गई एक अनूठी पहल है— का मकसद देश के हर कोने से त्याग, साहस और जन-भागीदारी की उन सैकड़ों कहानियों को सामने लाना है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

संस्कृति मंत्रालय ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इन कम ज्ञात कहानियों पर दस लघु फिल्में भी बनाई हैं। ये सभी पहलें हमें याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र तब और मजबूत होता है जब संवैधानिक मूल्यों को सांस्कृतिक यादों, ऐतिहासिक जागरूकता और राष्ट्र के प्रति गहरे अपनत्व की भावना से बल मिलता है। अब तक, डीडीआर की समर्पित वेबसाइट पर 19,500 से अधिक कहानियां उपलब्ध हैं।

डीडीआर पहल में योगदान देने वाले संस्थानों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले एक स्वायत्त संगठन 'सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज़ एंड ट्रेनिंग' ने अहम भूमिका निभाई है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली बड़ी संख्या में कहानियों को संकलित और व्यवस्थित किया है।

संस्कृति मंत्रालय ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इन कम ज्ञात कहानियों पर दस लघु फिल्में भी बनाई हैं। ये सभी पहलें हमें याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र तब और मजबूत होता है जब संवैधानिक मूल्यों को सांस्कृतिक यादों, ऐतिहासिक जागरूकता और राष्ट्र के प्रति गहरे अपनत्व की भावना से बल मिलता है। अब तक, डीडीआर की समर्पित वेबसाइट पर 19,500 से अधिक कहानियां उपलब्ध हैं

इस मौके पर हमारे साथ दो ऐसे जीवित स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं जो साहस, त्याग और सेवा की जीती-जागती मिसाल हैं:

महाराष्ट्र के श्री शेषराव लक्ष्मणराव खोट, जो एक युवा छात्र के तौर पर हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए थे।

आंध्र प्रदेश के श्री एड्डुला सूर्यनारायण रेड्डी, जिन्होंने बचपन में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना करना शुरू कर दिया था और ग्यारह साल की उम्र में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि आजादी कोई पिछली बात या बीता हुआ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है।

विरासत और सांस्कृतिक निरंतरता

यह 'विरासत' का तीसरा संस्करण है, जो उन सांस्कृतिक परंपराओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों और साझा विरासत का जश्न मनाता है, जिन्होंने पीढ़ियों के बीच संवाद, विविधता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दिया है। यह स्वतंत्रता सेनानी, सांस्कृतिक दूरदर्शी और संस्था निर्माता कमलादेवी चट्टोपाध्याय की स्मृति को सम्मान देता है।

शास्त्रीय प्रस्तुतियां उन संगीत परंपराओं पर आधारित हैं जो पीढ़ियों, क्षेत्रों और विचारधाराओं के बीच सदियों के संवाद से विकसित हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत स्वयं निरंतरता, विविधता, अनुशासन और रचनात्मक स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रमाण है— ऐसे मूल्य जो एक जीवंत लोकतंत्र के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं।

'लोकनाद – जनजातीय समरसता का स्वर संगम' प्रस्तुति असम और पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाती है। विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगीत और नृत्य परंपराओं के माध्यम से यह हमारे गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक— 'विविधता में एकता'— के विचार को खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत कई तरह की पहचानों को समाहित करने की उसकी क्षमता में निहित है।

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है सीसीआरटी विद्वानों की विशेष विषय-आधारित प्रस्तुति, 'खामोशी से आवाज़ तक, अंधेरे से भोर तक' । भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा के माध्यम से यह डर और दमन से साहस, नवीनीकरण और लोकतांत्रिक पुनरुत्थान तक की यात्रा को दर्शाती है।

इस आयोजन के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 'महर्षि दयानंद सरस्वती कला गुरुकुल और कलाग्राम' की आधारशिला रखना है। इसे एक ऐसे केंद्र के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जहां भारत की कलात्मक विरासत का अध्ययन और अभ्यास किया जा सके। यह गुरुकुल प्रणाली की प्राचीन परंपरा से प्रेरित है।

जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए, उसी तरह सांस्कृतिक परंपराओं को भी ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो उन्हें बनाए रखें और उनका नवीनीकरण करें। इसी सिद्धांत के अनुरूप, 'सेवा पर्व' यह दिखाता है कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का लोगों की चेतना और नागरिक बोध पर आज भी गहरा प्रभाव है। ■

नारी शक्ति का दशक
विकसित भारत का उत्कर्ष

अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

देश के किसी भी गांव, बस्ती या सुदूर इलाके में जाइए- हर घर की रसोई में एक जैसी बदली हुई हवा महसूस होगी। चूल्हे के जिस काले धुएं ने कभी नई दुल्हन की आंखों में आंसू भरे थे, उज्ज्वला की नीली लौ ने उसे विदा कह दिया है। जो मां कभी कोसों दूर से पानी ढोती थी, आज उसकी बेटी के पास 'हर घर जल' का अपना नल है। खेत के पीछे की वह शर्मनाक मजबूरी अब इतिहास है- आंगन में स्वच्छ भारत का शौचालय गरिमा के साथ खड़ा है। सिर पर पक्की छत है और उसके मालिकाना हक पर पहली बार- घर की महिला का नाम लिखा है। पर्स में जन-धन की पासबुक है और फोन में यूपीआई का ऐप है।

यह किसी पोस्टर पर छपी कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बारह वर्षों में महिला सशक्तीकरण का एक ऐसा सच है, जिसे देश की करोड़ों महिलाएं हर रोज़ जी रही हैं। यह उस दौर की दास्तान है जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास के विजन के साथ भारतीय नारी 'विकसित भारत' की शिल्पकार बन रही है।

इस बदलाव की विशालता को समझने के लिए एक दशक पीछे लौटिए। एक समय मातृ मृत्यु दर 212 थी। निर्भया जैसी घटना पर देश का आक्रोश सड़कों पर था, लेकिन व्यवस्था में नीतिगत इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती थी। महिला आरक्षण विधेयक 1996 से चार बार अधर में लटका रहा और ट्रिपल तलाक पर दशकों तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। चूल्हा सांसों में कालिख घोलता था। दूरस्थ हैंडपंप रोज़मर्रा की बेबसी का प्रतीक था। भारतीय नारी एक नई सुबह की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की उम्मीद बचाए हुए थी।

शुरुआत करते हैं सबसे पवित्र आंकड़े—जीवन का अधिकार से। देश में मातृ मृत्यु दर तेजी से घटकर 212 से 88 पर आ गई है। यूएन-एमएमईआईजी के अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में महज़ 48% की कमी आई, वहीं भारत ने 86% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। संस्थागत प्रसव 38.7% से बढ़कर 90.6% हो चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने चार करोड़ से अधिक माताओं के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित कर सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बचपन की नींव मजबूत की है।

देश में बने 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों ने महिलाओं को गरिमा दी। 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों ने धुएं से मुक्ति दी। आज 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है, जबकि 2014 में महज 17% परिवारों के पास यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी रिकॉर्ड्स पर मां-बहनों का नाम गर्व से दर्ज है।

गरिमा से स्वामित्व आया और स्वामित्व ने निर्णय लेने का आत्मविश्वास दिया। आर्थिक भागीदारी का यह विस्तार बैंक खाते से शुरू होकर उद्यमिता तक पहुंचा है। लगभग 56 करोड़ जन-धन खातों में 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।

विश्व बैंक मानता है- भारत ने एक दशक में खाता-स्वामित्व के जेंडर गैप को शून्य पर ला दिया है, जो वैश्विक वित्तीय समावेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋणों में से 68% ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्टैंड-अप इंडिया ने महिला उद्यमियों को 43,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं और 'दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई है। निर्धारित समय से पहले 3 करोड़

देश में बने 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों ने महिलाओं को गरिमा दी। 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों ने धुएं से मुक्ति दी। आज 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है, जबकि 2014 में महज 17% परिवारों के पास यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी रिकॉर्ड्स पर मां-बहनों का नाम गर्व से दर्ज है

बहनें 'लखपति दीदियां' बन चुकी हैं।

यह बदलाव शिक्षा और रोजगार में भी स्पष्ट है। देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 47.6% तक पहुंच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 4.53 करोड़ खातों में 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। उच्च शिक्षा में हमारा जेंडर समानता सूचकांक 1 के पार है और स्टेम शिक्षा में बेटियों की भागीदारी 43% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है।

यह परिवर्तन केवल अनुभवों में नहीं एसआरएस, एनएफएचएस, पीएलएफएस, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र— हर रिपोर्ट एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैः भारतीय महिला के लिए पहुंच बढ़ी है और आत्मनिर्भरता का नया आसमान खुला है।

इसी आर्थिक-सामाजिक चेतना का विस्तार राजनैतिक और लोकतांत्रिक भागीदारी में दिख रहा है। वर्ष 2019 के आम चुनावों में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 31.2 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया— यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी थी। इसी के फलस्वरूप दशकों से लंबित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' संसद में ऐतिहासिक सर्वसम्मति से पास हुआ। आज जमीनी स्तर पर 14.5 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं। देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में भी महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं और नौसेना की कमान संभाल रही हैं।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने ट्रिपल तलाक पर प्रभावी रोक लगाई, जिससे ऐसे मामलों में 82% की कमी आई है। देशभर में स्थापित 973 वन स्टॉप सेंटर्स पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी सहायता और काउंसलिंग मिल रही है। महिला हेल्पलाइन -181 ने अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की मदद की है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी— ये नारी-नेतृत्व वाले भारत की रीढ़ हैं।

बेशक, महिला सशक्तीकरण की राह में अभी भी चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके साथ ही, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आगामी परिसीमन की प्रक्रिया की प्रतीक्षा में है।

हमारे गणतंत्र के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला अब नीति निर्धारण के पटल पर केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उसकी सक्रिय 'सह-निर्माता' है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वह अब राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया की सहयात्री है, सहभागी है और सूत्रधार भी। ■

भाजपा को जानें

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा को साझा किया

'भाजपा को जानें' पहल के तहत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 26 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में यूरोपीय संघ (ईयू) के 23 सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों तथा भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत के साथ संवाद किया।

भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत ने 'भाजपा को जानें' पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से भारत की लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। उन्होंने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर हुई बातचीत के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे भारत-ईयू साझेदारी का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

संवाद के दौरान श्री नितिन नवीन ने भाजपा के ऐतिहासिक सफर, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे तथा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उसकी विकास यात्रा से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। उन्होंने पार्टी के जमीनी स्तर पर मजबूत जनसंपर्क, अनुशासित संगठनात्मक संरचना तथा जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया।

श्री नवीन ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार तथा आम नागरिकों को सशक्त बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), सेमीकंडक्टर विकास तथा अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत के बढ़ते फोकस का भी उल्लेख किया।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी तथा भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी उपस्थित रहे। ■

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: भारत की सनातन धरोहर से विश्व कल्याण तक

संजय सेठ
रक्षा राज्य मंत्री

21 जून, 2026 को सम्पूर्ण विश्व 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है — 'स्वस्थ आयु के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing)। यह विषय केवल एक वार्षिक अभियान का संदेश नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक जनसांख्यिकी, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ, सक्रिय एवं गरिमामय जीवन की आवश्यकता का वैश्विक उत्तर है।

विशेष महत्व की बात यह है कि जिस समय भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, विकास, सेवा और जनकल्याण के 12 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव मना रहा है, उसी समय विश्व 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भी साक्षी बन रहा है। यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि उस परिवर्तनकारी दृष्टि का प्रतीक है जिसने भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया।

कोलकाता से विश्व तक : योग का महोत्सव

इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हो रहा है, जहां स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी लाखों योग साधकों के साथ योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस आयोजन में अभूतपूर्व जनभागीदारी के माध्यम से नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

देशभर में दिल्ली के लाल किला, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, हरिद्वार के हर की पौड़ी, अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट सहित 12 प्रतिष्ठित स्थलों पर विशेष योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

वहीं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के लगभग 2,500 स्थानों पर भारतीय दूतावासों, सामुदायिक संगठनों और योग संस्थाओं के सहयोग से योग दिवस मनाया जा रहा है। यह दर्शाता है कि योग आज केवल भारत का नहीं, सम्पूर्ण मानवता का साझा सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी आंदोलन बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी : योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले युगद्रष्टा

सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारत की प्राचीन योग परंपरा को विश्व मंच पर स्थापित कर उसे वैश्विक जन-कल्याण का माध्यम बनाया।

27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था— "Yoga is an invaluable gift from our ancient tradition. Yoga embodies unity of mind and body, thought and action." (योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अनमोल उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म की एकाग्रता का प्रतीक है।)

प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक आह्वान को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। मात्र ढाई महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिकॉर्ड 177 देशों के समर्थन के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी प्रस्ताव को प्राप्त यह सबसे व्यापक समर्थन था।

21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब से योग मानवता को जोड़ने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में निरंतर विस्तार प्राप्त कर रहा है।

आज 180 से अधिक देशों में योग दिवस का आयोजन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, सॉफ्ट पावर और प्रधानमंत्री मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व की प्रभावशीलता का जीवंत प्रमाण है।

योग : भारत का सबसे बड़ा सभ्यतागत योगदान

योग शब्द संस्कृत की 'युज्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है— जोड़ना, मिलाना, एकत्व स्थापित करना।

योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है।

महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा -
"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।"

अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध, विचारों का संतुलन और मन की स्थिरता ही योग है।

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण योग को जीवन-दर्शन के रूप में

मात्र ढाई महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिकॉर्ड 177 देशों के समर्थन के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी प्रस्ताव को प्राप्त यह सबसे व्यापक समर्थन था। 21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब से योग मानवता को जोड़ने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में निरंतर विस्तार प्राप्त कर रहा है

प्रस्तुत करते हैं - "योगः कर्मसु कौशलम्।"

अर्थात् कर्मों को उत्कृष्टता और समभाव के साथ करना ही योग है।

इसी प्रकार - "समत्वं योग उच्यते।"

अर्थात् सुख-दुःख, लाभ-हानि और सफलता-असफलता में संतुलित रहना ही योग है।

यही कारण है कि योग आज तनावग्रस्त, विभाजित और तेज़ी से बदलती दुनिया को संतुलन, शांति और आत्मबोध का मार्ग प्रदान कर रहा है।

योग और आयुष : भारत की ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 नवंबर, 2014 को आयुष विभाग को पूर्ण मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया।

यह निर्णय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों – योग, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी – को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ।

आज आयुष क्षेत्र करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का आधार बन चुका है। गुजरात के जामनगर में स्थापित WHO Global Centre for Traditional Medicine भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

'Heal in India', आयुष वीज़ा, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता जोर भारत को विश्व का अग्रणी वेलनेस हब बना रहा है।

विकसित भारत @2047 और योग की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सामने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है।

यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति का नहीं, बल्कि स्वस्थ, सक्षम, आत्मविश्वासी और उत्पादक समाज के निर्माण का भी संकल्प है।

एक स्वस्थ नागरिक ही विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होता है। योग और आयुर्वेद इसी दृष्टि के सबसे प्रभावी साधन हैं। योग न केवल रोगों की रोकथाम करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उत्पादकता और जीवन-गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसलिए योग विकसित भारत की मानव पूंजी को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 : 'स्वस्थ आयु के लिए योग' क्यों महत्वपूर्ण है?

इस वर्ष की थीम 'Yoga for Healthy Ageing' वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकता को संबोधित करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले दशकों में वृद्धजन आबादी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में केवल लंबा जीवन पर्याप्त नहीं है; स्वस्थ, सक्रिय और स्वावलंबी जीवन अधिक महत्वपूर्ण है।

योग –

- शारीरिक संतुलन और लचीलापन बढ़ाता है,
- अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है,
- रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है,
- तनाव, अवसाद और चिंता को कम करता है,
- स्मरण शक्ति और मानसिक एकाग्रता को बनाए रखने में सहायता करता है,
- वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

इसी संदर्भ में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा है कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा के इस युग में स्वस्थ और गरिमामय वृद्धावस्था की कला सीखना आवश्यक है, और योग इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

12 वर्ष सरकार के, 12 वर्ष योग दिवस के

वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक संगम का वर्ष है।

एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास, सुशासन, स्वास्थ्य, डिजिटल परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के 12 वर्षों का उत्सव मना रहा है।

दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी अपने 12वें संस्करण में प्रवेश कर चुका है।

इन दोनों यात्राओं का मूल भाव समान है– भारत की प्राचीन शक्ति को आधुनिक विश्व के कल्याण से जोड़ना।

जिस प्रकार पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसी प्रकार योग ने भी विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श किया है।

यह 12 वर्ष केवल एक कार्यक्रम की सफलता नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और वैश्विक नेतृत्व की विजयगाथा हैं।

योग : एक दिवस नहीं, जीवन-पद्धति

आज आवश्यकता है कि हम योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखें।

योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने परिवार, विशेषकर बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को योग से जोड़ें। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला योग ही बन सकता है।

आइए, हम सब संकल्प लें कि योग को केवल उत्सव नहीं, जीवन का संस्कार बनाएंगे।

भगवद्गीता के शब्दों में – "योगः कर्मसु कौशलम्।"

अर्थात् योग को जीवन-कौशल बनाकर हम स्वयं को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को अधिक सक्षम, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं।

अंत में वैदिक भावना के साथ –

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥

अर्थात् सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगल का अनुभव करें और कोई भी दुःख का भागी न बने।

इसी मंगलकामना के साथ –

जय हिन्द!
जय भारत! ■

आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है: नरेन्द्र मोदी

40 सी-295 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एयरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जून को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 135वीं कड़ी की शुरुआत करते हुए कहा कि 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने 'मन की बात' में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौ सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौ सेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिज़ाइन और निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है।

'मेड इन इंडिया' सी-295 विमान ने पूरी की अपनी पहली उड़ान

श्री मोदी ने कहा कि जून के महीने में ही विमानन क्षेत्र में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। सी-295, ये विमान 'मेड इन इंडिया' है और सी-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एयरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल' का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग के साझेदारों ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।

उन्होंने कहा कि जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस'। इस बार दुनिया के 2,500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान-स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित 'विश्व योगासन चैम्पियनशिप' की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। भारत इस चैम्पियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन-भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन-भागीदारी का हम बार-बार अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो, कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। श्री मोदी ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रीसायकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि कार पूलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने-अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, इस वैश्विक संकट का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन-भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण भाजपा केंद्रीय कार्यालय परिवार के सदस्यों के साथ 28 जून, 2026 को नई दिल्ली में अपने आवास पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के 'मन की बात' कार्यक्रम का 135वां एपिसोड सुनते हुए

देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर दो लाख रुपये तक का 'दुर्घटना बीमा' मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है।

उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुःखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है। मतलब एक दिन का मुश्किल से डेढ़ रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। ये आकड़ें बहुत बड़े हैं। इन आकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी-अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया।

श्री मोदी ने कहा कि कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे-से कदम से हो सकती है, छोटा-सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है— अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता। वो डर पैदा करता है और जब डर मन पर हावी हो जाता है, तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं, जिनका बड़ा नुकसान होता है।

बिल्कुल ना खरीदें प्लास्टर ऑफ़ पेरिस से बनी मूर्तियां

श्री मोदी ने कहा कि मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय 'गणेश उत्सव' से जुड़ा है। वैसे तो 'गणेश उत्सव' में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल, गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है। आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसायटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो।

उन्होंने कहा कि जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल ना खरीदें।

उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है। हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार 'गणेश उत्सव' में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश-हित में कदम भी उठाएंगें।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे छोटे-बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आस-पास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए। अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए, हो सकता है आपके आस-पास की कोई छोटी-सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। ■

नई दिल्ली में 23 जून, 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह–II
(पद्म पुरस्कार–2026) में शामिल होतीं माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सेशेल्स में 28 जून, 2026 को सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सेशेल्स में 27 जून, 2026 को सेशेल्स कोस्ट गार्ड बेस पर फास्ट पेट्रोल वेसल, कार एवं एम्बुलेंस को सौंपने के कार्यक्रम के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी

सेशेल्स में 27 जून, 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत करते भारतीय समुदाय के प्रतिनिधिगण

नई दिल्ली में 23 जून, 2026 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एवं वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

@Kamal.Sandesh
kamal.sandesh
@KamalSandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 15 जुलाई, 2026
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

छायाकार: अजय कुमार सिंह